● वर्ष-2
● अंक-254
रायपुर, गुरुवार 15 जून 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

विपक्षी एकता की राह में फूल और कांटे

तीन राज्यों के मुख्यमंत्री केसीआर, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी बैठक से नदारद रहेंगे

हिमांशु मिश्रा

आज से ठीक नौ दिन बाद यानी 23 जून को पटना में विपक्ष का एक बड़ा कुनबा जुटेगा। लगभग सभी बड़े विपक्षी दलों के नेता शिरकत करेंगे। इस बैठक के जरिए देश को एक बड़ा सियासी संदेश देने की तैयारी है। संभव है कि यहीं से इस बात का भी आधिकारिक एलान हो जाए कि भाजपा के खिलाफ अगला लोकसभा चुनाव विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ेंगे।

कौन, कहां से कितनी सीट पर लड़ेगा? पूरे विपक्ष की अगुआई कौन करेगा? क्या चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित हो जाएगा? अगर हां तो कौन विपक्ष से पीएम पद का उम्मीदवार होगा? इस तरह से सवालों पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे भी दल हैं, जो इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे?

एकजुटता के लिए विपक्ष की रणनीति

विपक्ष अभी उन मुद्दों की तलाश रहा है, जिनके सहारे सभी के बीच सहमति बन सके। अभी तक कुछ मुद्दे ऐसे सामने आए हैं, जिनको लेकर लगभग सभी दल एकसाथ हैं। इनमें विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से लेकर सरकार पर सांप्रदायिक होने तक के आरोपों पर इन दलों में एका होता दिख रहा है। विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे पर भी एकजुट होते दिख रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा की सरकार क्षेत्रीय और विपक्ष के अन्य राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसे भी विपक्ष एकजुट होने के लिए मुद्दा बना सकता है।

सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा?

अब तक की चर्चा में कहा जा रहा है कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाएगा। मसलन बिहार में राजद-जदयू का प्रभाव है। ऐसे में यहां की ज्यादातर सीटों पर इन्हीं दो पार्टियों के उम्मीदवार उतारे जाएं। इसके अलावा अन्य पार्टी जिसका कुछ जनाधार हो, उन्हें भी कुछ सीटों पर मौका दिया जाए।

इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। राजस्थान-छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने, वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है।

विपक्ष के गठबंधन का हिस्सा

कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी वाम दल, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), एनसीपी, टीएमसी, झामुमो, आम आदमी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोकदल, आरएलडी, डीएमके जैसे दलों के नेता 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में शामिल हो सकते हैं। ये दल शुरुआती गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं।

बैठक में शामिल नहीं होंगे

कई ऐसे दल हैं जिन्होंने 23 जून को होने वाली बैठक से किनारा कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा नाम तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का है। केसीआर की पार्टी बीआरएस ने इस बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है। अभी बीआरएस तेलंगाना की सत्ता में है और कांग्रेस यहां विपक्ष में है। दोनों के बीच सीधी टक्कर होती है। वहीं, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी विपक्ष के इस बैठक में नहीं आएंगे। इसके अलावा यूपी में सुभासपा, बिहार में हम जैसे छोटे दल भी हैं, जो विपक्षी एकता से अलग राह पकड़ सकते हैं।

एकजुट नहीं हुआ तो क्या पड़ेगा असर?

वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं, अगर विपक्ष के सभी दल साथ नहीं आते हैं तो इसका सीधा असर विपक्ष के गठबंधन और फिर सीटों पर पड़ेगा। विपक्ष के बिखराव का फायदा भाजपा को मिल सकता है। मसलन यूपी में ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट पूरी तरह से खत्म हो गया है। बसपा के पास अभी भी बड़ी संख्या में कैडर वोट हैं। अगर यूपी में बसपा अलग चुनाव लड़ती है तो कई सीटों पर वह विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा को ही फायदा मिलेगा। इसी तरह तेलंगाना, बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों में भी विपक्ष के इस गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

2019 में भी हो चुका है विपक्षी एकता का प्रयास

यह कहना अधिक उचित होगा कि जब-जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, विपक्षी एकता का बिगुल बजाने लगता है। खासकर, नरेंद्र मोदी को बेदखल करने के लिए उसकी यह कोशिश होती है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस तरह के प्रयास हुए थे। तब राहुल गांधी भी खुल कर विपक्ष के साथ थे।

इन दिनों ✍ **शशांक शर्मा**

कांग्रेस के लिए 75 पार की चुनौती

छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है। इधर प्रदेश में भी कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, संगठन की बैठकों का दौर जारी है। सत्तारूढ़ पार्टी में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल भी जरूरी होता है और कांग्रेस की बात करें तो बड़े नेताओं के बीच आपसी खींचतान का भी असर होता है। 2003, 2008, और 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का एक महत्वपूर्ण कारण नेताओं की आपसी लड़ाई और इसके चलते एक दूसरे को निपटाने की प्रवृत्ति भी था। अभी संभागीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को स्पष्ट भी किया कि अजीत जोगी के गुट की महत्वाकांक्षा के चलते चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। अब स्थिति बदल गई है, पार्टी नई पीढ़ी के हाथों है और इस पीढ़ी के नेताओं की महत्वाकांक्षा कोई कम नहीं है इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के बीच सामंजस्य जरूरी है। लेकिन जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन को तक पर रखकर सत्ता केंद्रित चुनाव की रणनीति बनती है। इस कारण कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी होती है। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी अपने क्षेत्रों में अपना महत्व चाहते हैं। जांजगीर, चांपा, कोरबा और बिलासपुर में डॉ. चरणदास महंत तथा सरगुजा में मंत्री टी एस सिंहदेव के नेतृत्व में पिछला चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था। अब इनको ज्यादा महत्व नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। टी एस सिंहदेव तो मुख्यमंत्री पद के ढ़ाई ढ़ाई साल के फॉर्मूले के अमल नहीं होने के कारण भी नाराज हैं। इधर वरिष्ठ नेताओं में सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, ताम्रध्वज साहू को भी साधना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा अपनी पार्टी के भीतर भी चुनौती मिलेगी। पार्टी को इन दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। इधर पिछले चुनाव में 68 सीटों पर जीत हासिल करके और फिर लगातार उपचुनाव जीतकर पार्टी को जीतने की आदत लग गई है। यही कारण है कि संगठन के भीतर अगले चुनाव में 75 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के नारे लग रहे हैं। कांग्रेस संगठन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, वर्तमान में 71 विधायकों के काम काज का भी आंकलन किया जा रहा है। कांग्रेस की बड़ी जीत ही अगले चुनाव में एक चुनौती बनेगी क्योंकि कई नए विधायकों के प्रदर्शन के आधार पर टिकट कटने की बात आयेगी और विधायक का टिकट काटना मुश्किल भरा निर्णय होता है। अगर टिकट नहीं कटी तो जनता की नाराजगी झेलनी पड़ेगी और टिकट कटी तो विधायक और उसके समर्थकों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। आजकल पहली बार के विधायक भी धन से ताकतवर हो जाते हैं और अपना एक छोटा गुट अपने क्षेत्र में बना लेते हैं। इन चुनौतियों को पर करके ही कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी।

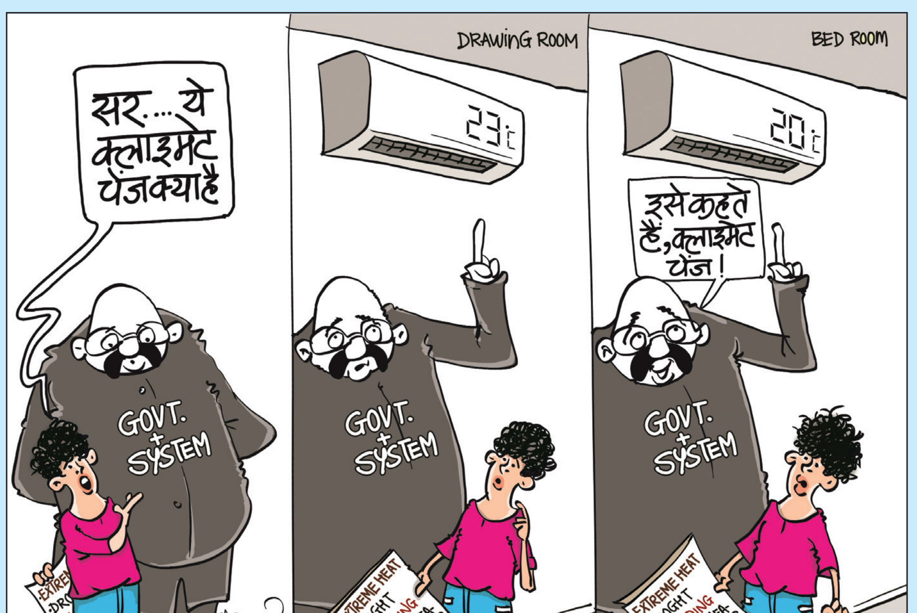

इस साल 6500 अमीर लोग छोड़ सकते हैं भारत

नई दिल्ली। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट (2023) के नए अध्ययन में दावा किया गया है कि इस साल 6500 अल्ट्रा रिच भारत छोड़ सकते हैं। इन अल्ट्रा रिच के लिए अधिक तकनीकी शब्द हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स है और यह इतने अमीर लोगों को संदर्भित करता है कि उनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की निवेश योग्य संपत्ति है। रुपये के लिहाज से उस सीमा का मतलब 8.2 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। हालांकि ये संख्या पिछले साल साढ़े सात हजार हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स के छोड़कर जाने वाले आंकड़ों से कम है। 2023 में भारत का संभावित शुद्ध बहिर्वाह यानी अपना वतन छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसने के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है।

रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए जो आंकड़ा पेश किया गया है, अगर वह सच साबित हो जाता है, तो चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश होगा, जहां से इतनी बड़ी संख्या में अमीर पलायन करके दूसरे देश चले जाएंगे। हेनले की वार्षिक प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट मेंअल्ट्रा रिच की श्रेणी में ऐसे लोगों को रखा गया है, जो किसी दूसरी जगह कम स`कम एक मिलियन डॉलर या 8.2 करोड़ रुपये का निवेश करने में सक्षम हैं. इस निवेश में किसी की परिसंपत्त, नकदी या शेयर जैसी चीजें शामिल हैं. इसमें देनदारियों को शामिल नहीं किया गया है. हेनले की रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए जो आंकड़ा पेश किया गया है, वह अगर सच साबित होता है, चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरा ऐसा देश होगा, जहां से सबसे अधिक अति धनाढ्य लोग वतन छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएंगे।

किस देश से कितने अमीर छोड़ सकते हैं अपना देश

दुनियाभर में वेल्थ और इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन पर नजर रखने वाली हेनले की रिपोर्ट में बताया गया कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की ओर रूख करने वालों में सबसे ज्यादा चीन आगे हैं, जहां इस साल साढ़े 13 हजार अमीरों का पलायन का अनुमान है। इस सूची में तीसरे स्थान पर ब्रिटेन है, जहां से इस वर्ष 3200 करोड़पति देश छोड़ सकते हैं। वहीं रूस से 3 हजार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के दूसरे देशों में जाने का अनुमान है और ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है।

अमीरों की सर्वोच्च प्राथमिकता

राजनीतिक स्थिरता, कम कराधान, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमेशा करोड़पतियों के लिए प्रमुख मैट्रिक्स रहे हैं जब यह तय करने की बात आती है कि कहाँ रहना है। हालाँकि, संपन्न व्यक्तियों की प्राथमिकताएँ अमूर्त लेकिन समान रूप से उनके बच्चों की संभावनाएं, उनके जीवन की गुणवत्ता, और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रभाव डाल रही है।

प्रमुख समाचार

राहुल गांधी के खिलाफ एक और मानहानि का मामला

बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मानहानि मामले में चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रहा हैं। इन सब के बीच भाजपा की ओर से उनके खिलाफ एक और मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। इस बार यह मामला कर्नाटक का है। जानकारी के मुताबित भाजपा ने बेंगलुरु में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की है। बीजेपी की छवि खराब करने वाले विज्ञापनों में झूठे दावों का आरोप लगाने वाली निजी शिकायत पार्टी के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने 9 मई को दायर की थी। एस केशव प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने उनकी पार्टी पर झूठे आरोप लगा कर उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है।

झारखंड में भी बीजेपी की स्टार वसुंधरा राजे का जलवा

रांची। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राजे भाजपा की योजना में वापस आ गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी द्वारा प्रदेश से दूर झारखंड में तैनात किया गया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में नौ साल पूरे होने के मौके पर देश भर में भाजपा के प्रचार अभियान के तहत राजे ने मंगलवार को गोड्डा में एक रैली की है। योजना है कि भाजपा के शीर्ष नेता देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों को कवर करें। राजे को झारखंड के गिरिडीह, दुमका, गोड्डा और कोडरमा लोकसभा क्षेत्रों का जिम्मा सौंपा गया है। इस लिहाज से मंगलवार की रैली आश्चर्यजनक नहीं है। महत्वपूर्ण था वह यह था कि कई वर्षों में यह शायद पहली बार था जब भाजपा ने राजे को राजस्थान के बाहर इस तरह के कार्यक्रम में शामिल किया। देश भर में हुए दर्जनों विधानसभा चुनावों के साथ-साथ उपचुनावों में, राजे को भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं किया गया है।

25 मांगों को लेकर खाप पंचायतों का हरियाणा बंद

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद गिरफ्तारी की मांग कर रहे है। इसके अलावा एमएसपी की मांगों समेत खाप पंचायतों ने कई मांगों को लेकर बुधवार 14 जून को हरियाणा बंद का ऐलान किया है। इस बंद के कारण दिल्ली में दूध, फल और सब्जी की सप्लाई भी बंद हो गई है। खाप पंचायतों ने पहले ही सप्लाई बंद करने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली का पानी भी बंद के दौरान खाप पंतायतों ने रोका है। खाप पंचायतों ने तीन दिन पहले सर्वसम्मति के साथ हरियाणा बंद किए जाने के संबंध में फैसला लिया था और इसकी सूचना दी थी। वहीं इस प्रदर्शन के मद्देनजर पूरे हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इस प्रदर्शन को देखते हुए राज्य के कई जिलों अधिक गंभीर स्थिति होने की संभावना है।

शुभेंदु ने राजीव सिन्हा को बताया ममता का पालतू

बंगाल। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव आयोग के दफ्तर में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे। इतना ही नहीं अलग-अलग इलाकों से भाजपा कार्यकर्ता-समर्थक बस से पहुंचे हैं। इनका नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार कर रहे हैं। कोलकाता में आयोग के कार्यालय में इस समय गहमागहमी का माहौल है। शुभेंदु ने रस्सी हटा दी और बैरिकेड हटा दिए ताकि भाजपा नेता और कार्यकर्ता आयोग के कार्यालय में प्रवेश कर सकें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 20 हजार सीटों पर निर्विरोध जीतने के लिए ममता बनर्जी और राजीव सिन्हा ने साजिश की है। उन्होंने सेंट्रल फोर्स के लिए मना कर दिया।

रफ्तार से गुजरात तट की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय

अहमदाबाद। चक्रवात बिपारजॉय गुजरात तट की ओर तेजी से बढ़ा, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। प्राधिकारियों ने अब तक कच्छ जिले में जखाऊ बंदरगाह के पास चक्रवात की संभावित भूमि से पहले गुजरात के तटीय क्षेत्रों से 50,000 लोगों को अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया है। इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात %बिपारजॉय% के प्रभाव से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीनों सेना प्रमुखों से बात की और चक्रवात %बिपारजॉय% के लैंडफॉल के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की। सशस्त्र बल नागरिक अधिकारियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। गुजरात के कच्छ जिले के जखाऊ बंदरगाह के पास शक्तिशाली चक्रवात 'बिपारजॉय' की संभावित दस्तक से पहले अधिकारियों ने राज्य के तटीय इलाकों से अब तक लगभग 50 हजार लोगों को निकालकर अस्थायी आश्रय शिविरों में स्थानांतरित किया है।

जाति की सियासी बिसात पर राजस्थान

प्रभु चावला

राजस्थान का अतीत षड्यंत्रों, लड़ाइयों और दिलचस्प प्रेम कथाओं से हुआ भरा है। पुराने समय में जहां लड़ाइयां शौर्य के दम पर लड़ी जाती थीं, आज वहां जाति सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। हालांकि, दरबारी गप्पबाजी का चरित्र पहले जैसा ही है। अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों से कहीं अधिक चर्चा बंद कमरों में बातचीत और चौराहों पर लगने वाली अटकलों की हो रही है, कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी गहलोत या उनसे उम्र में छोटे उत्तराधिकारी को चुनौती देने के लिए वसुंधरा राजे को मैदान में उतारेगी।

मगर दोनों ही खेमों में, योग्यता पर जाति भारी पड़ती है। कांग्रेस फिर सुर्खियों में है। पूर्व उपमुख्यमंत्री, 45 वर्षीय सचिन पायलट, पहले अपने लिए और उसके बाद पार्टी के लिए समर्थन जुटाने सड़क पर उतरते रहे हैं। वे अपना मकसद जमीनी कार्यकर्ताओं से संपर्क और वसुंधरा सरकार के समय भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई की मांग बताते हैं। मगर, उनका असल निशाना गहलोत हैं। पायलट ने अपनी पार्टी और अपने संरक्षकों को यह समझाया है कि वह आलाकमान से केवल यह कह रहे हैं कि वे चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने के वादे को पूरा करे। मगर आलाकमान को लगता है कि उम्र सचिन के पक्ष में है, वह थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं। उसने पायलट को गहलोत सरकार को अस्थिर करने की उस नाकाम कोशिश के लिये माफ नहीं किया है, जब वे 19 विधायकों को लेकर बाहर चले गये थे। इस कदम के पीछे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग बताया जा रहा था। मगर कांग्रेस के भीतर जारी रस्साकशी में जाति असल कारण है।

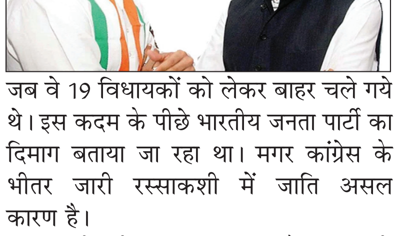

गहलोत ने 1998, 2008 और 2018 में तीन बार अपना कार्यकाल पूरा कर पहले ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह 1998 में जब मुख्यमंत्री बने थे तब केवल 47 वर्ष के थे। वे राजस्थान में पिछड़ी जाति (माली) के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने प्रदेश की राजनीति में ऊपरी जाति का दबदबा खत्म कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तब पटखनी दी थी, जब उस पर ताकतवर ठाकुर नेता भैरों सिंह शेखावत का नियंत्रण था। पायलट जाति और योग्यता दोनों के आधार पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। उनके पास डिग्री भी है और वंश का नाम भी। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं और विदेश में पढ़े हैं।

कांग्रेस ने उन्हें भारत का सबसे युवा केंद्रीय मंत्री ही नहीं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। मगर अपने पिता से अलग, जो राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी थे, सचिन ने जाति और समुदाय की विरोधाभासी राजनीति को चुना। राजेश पायलट को अपनी सीमाओं का अंदाजा था और इसलिए वह राज्य की राजनीति से किनारा कर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेता बने। मगर सचिन ने राजस्थान को अपनी कर्मभूमि और रणभूमि दोनों बनाया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2018 में लगभग 100 सीटें जीतीं, जिसके बाद वे राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल हो गये।

मगर नीति निर्धारकों के बीच स्वीकार्यता की बदौलत गहलोत दौड़ में आगे रहे। कांग्रेस के कई नेताओं को लगता है कि सचिन राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और वह खुद को प्रदेश में बांधकर अपनी योग्यता बर्बाद कर रहे हैं। उनका अनुमान है कि गांधी परिवार की युवा पीढ़ी के साथ उनकी घनिष्ठता है, जिससे पार्टी में उनका कद तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, गांधी परिवार यह तो समझता है कि सचिन का युवा होना और स्वच्छ छवि पार्टी के लिये एक पूंजी है, मगर उनकी जाति बोझ बन जाती है। वे गूजर समुदाय से हैं, जिनकी राज्य की आबादी में हिस्सा दो अंकों में भी नहीं पहुंचता। सचिन की सबसे बड़ी भूल अपनी पहचान गूजर समुदाय से जोड़ना थी, जब वे गूजरों को अनुसूचित जनजाति का दर्ज दिलाने की मांग को लेकर जेल गये। ऐतिहासिक तौर पर गूजर, जाट और ठाकुर एक-दूसरे को पसंद नहीं करते। ठाकुरों ने गूजरों की कीमत पर फायदा उठाया, जबकि जाट अभी भी सत्ता में हिस्सेदारी के लिये लड़ रहे हैं। यह बस संयोग भर नहीं है कि राजस्थान में आज तक कोई गूजर या जाट मुख्यमंत्री नहीं हुआ।

आजादी के बाद से प्रदेश में बने 28 अंतरिम या औपचारिक मुख्यमंत्रियों में से, 24 कांग्रेस से थे।

वन अधिकार पट्टेधारियों को सभी योजनाओं का लाभ दिलवाएं: डॉ. टेकाम

आदर्श गांवों की सूची सभी विभागों को दी जाए तथा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करवाएं

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने वन अधिकार पत्र वितरण के प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सामुदायिक वन अधिकार, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र एवं वन अधिकार पत्र प्राप्त हितग्राहियों को मनरेगा के तहत् स्वीकृत कार्यों एवं अन्य आनुषंगिक कार्यों में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा है विशेष पिछड़ी जनजातियों के वन अधिकार पट्टेधारियों को सभी विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। इनके वन अधिकार पट्टे की भूमि पर मनरेगा के तहत अभिसरण से कार्य कराया जाए। जिला समन्वय समिति बनाकर विभागों को कार्य का लक्ष्य दिया जाए। जिन गांवों में वन अधिकार के अधिक पट्टे दिए गए हैं उन्हें आदर्श गांव घोषित कर इन वर्गो के लिए कार्य कराया जाए। आदर्श गांवों की सूची सभी विभागों को दी जाए तथा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करवाएं।

मंत्री डॉ. टेकाम आज यहां आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के सहायक आयुक्तो एवं परियोजना प्रशासकों को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभाग के सचिव श्री डी.डी.सिंह और आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी सहित वरिष्ट अधिकारी उपस्थित थे।वर्तमान में मौसम को देखते हुए वन अधिकार पट्टेधारियों की भूमि पर पौधा रोपण करवाएं। यहां सब्जी, फल के पौधो का वितरण भी किया जाए। विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह ने कहा कि गतवर्ष हर गांव में सामुदायिक भवन अधिकार पत्र वितरण का लक्ष्य दिया गया था, इस कार्य को भी पूरा करें। विशेष पिछड़ी जनजातियों के वन अधिकार पट्टेधारियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण, पेंशन योजना और राशनकार्ड वितरण कर लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही इन वर्गो के बच्चों के शिक्षा का विशेष ध्यान दें। आजीविका के लिए लघु वनोपज संग्रहण कार्य से भी जोड़ा जाए। वन अधिकार मान्यता के लिए आवेदकों की संख्या बढ़ाएं।

मंत्री डॉ. टेकाम ने विभागीय योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने, निर्माण कार्यो को स्थल पर निरीक्षण कर अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ केन्द्रीय योजनाओं के कार्यो को भी समय पर पूरा करें। देवगुड़ी आदिवासियों के आस्था का केन्द्र है। समुदाय का इससे जुड़ाव होना चाहिए। देवगुड़ी निर्माण के सभी स्वीकृत कार्यो को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त श्रीमती शम्मी आबिदी ने कहा कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लिए आवास भी बनाए जाने है, इसके लिए इन वर्गो के मुखिया और हितग्राहियों से चर्चा कर उनके संस्कृति के अनुरूप घर बनाया जाए। आवास का निर्माण वैध जमीन पर ही किया जाए और वहां बिजली पानी की मूलभुत सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2023-24 के लिए मेस संचालन, खेल सामग्री क्रय करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र पूर्ण कर ली जाए। इन विद्यालयों में कक्षा 10 वीं और 12 वीं के विद्यार्थियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिले के सहायक आयुक्त इसके लिए इन स्कूलों का अकादमी कैलेण्डर तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित करवाए। इन स्कूलों के शिक्षकों को विषय-वस्तु के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। इन स्कूलों के बच्चों का प्रत्येक माह यूनिट टेस्ट लेकर बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का आकलन करें। विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित क्रीडा परिसरों में स्वीकृत लघु निमार्ण कार्यो का मौके पर मुआयना कर इन कार्यो को शीघ्र ही पूरा करवाए। क्रीडा परिसरों में बच्चों की समय पर भर्ती हो। इन क्रीडा परिसरों में खेल विधाओं के अनुसार कैम्प लगाकर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाए।

बैठक में सहायक आयुक्तों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों एवं उन्नयन किये गए छात्रावास-आश्रमों की मौके पर जाकर समीक्षा करें। विभाग अंतर्गत संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अनुरक्षण, लघु मद अन्तर्गत किए गए कार्यो की समीक्षा भी की गई। बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की समीक्षा के अंतर्गत गणवेश आपूर्ति, पाठ्यपुस्तक तथा विद्यालयवार, शिक्षकवार बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं अतिथि शिक्षकों की भर्ती की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

भाजपा ने कांग्रेस को राम को मानने के लिए बाध्य किया : नारायण चंदेल

एमसीबी। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मनेंद्रगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीजीपीएससी परीक्षा 2021 के रिजल्ट में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए हैं। नारायण चंदेल ने रामसेतू को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा है।

नारायण चंदेल के निशाने पर कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस ने तो पहले रामसेतू को नकार दिया था। कहा था कि राम काल्पनिक हैं। रामायण एक कहानी है। कांग्रेसी रामायण को भी नहीं मानते थे और राम को भी नहीं मानते थे। भाजपा ने कांग्रेस को राम को मानने के लिए बाध्य किया है। भाजपा को देखकर कांग्रेसी राम को मान रहे हैं।

सीजीपीएससी एग्जाम में घोटाले का आरोप

छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सीजीपीएससी एग्जाम रिजल्ट में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीजीपीएससी में बड़ा घोटाला हुआ है। इस प्रदेश में नौजवानों की भावनाओं के साथ भूपेश सरकार ने खिलवाड़ किया है। आने वाले 19 जून को हम युवा मोर्चा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे हैं। वो एक लाख व्यक्ति नहीं, वो एक लाख परिवार हैं। यह कोई छोटा विषय नहीं है।19 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव- सीएम आवास के घेराव से पहले भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। भाजपा ने प्रदेश के नौजवानों और परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे सभी 19 जून को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए अपना समर्थन दें।

रमन सिंह का दावा, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का होगा सफाया

कवर्धा। क्रिकेट के मैदान पर भिड़ने से पहले धुर प्रतिद्वंद्वी माइंड गेम खेलते हुए एक दूसरे को कमजोर बताने की कोशिश करते हैं, ताकि अगले की रणनीति को कमजोर किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार पर घपले घोटाले का आरोप लगाने और भागवान राम के नाम पर घेरने के बाद अब भाजपा भी माइंड गेम खेलने पर उतर चुकी है। हर मोर्चे पर बघेल सरकार को कमजोर दिखाकर मतदाताओं को कन्फ्यूज करने की कोशिश हो रही है। इसी कन्फ्यूजन से कांग्रेसी वोट बैंक में सेंध लगाने की योजना है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय नेताओं के साथ ही केंद्र से आने वाला हर नेता अब इसी रणनीति पर चल रहा है।

चंद्रनाहुन समाज के कार्यक्रम में रमन ने किया ये दावा

कवर्धा में 10 जून को चंद्रनाहुन कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक सम्मेलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया होने का दावा किया। भूपेश सरकार पर हमला करते हुए रमन सिंह ने कहा कि ये जनता को गुमराह कर रहे हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनका काम छत्तीसगढ़ के विकास में बाधा पहुंचाना है। इसलिए भूपेश बघेल को धोखे में नहीं रहना चाहिए।

भाजपा के पास है केवल 14 सीटें

छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस के पास 71 तो भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सीट है। बाकी की 5 सीटों में से 3 जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और दो सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां कांग्रेस 75 से अधिक सीटें लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस का भ्रम करार दिया है।

फर्जी सेबी अधिकारी बनकर लाखों की ठगी, तीन गिरफ्तार

बीजापुर। साई प्रसाद कंपनी से ली गई पॉलिसी की राशि वापस दिलाने केनाम पर सेबी अधिकारी बनकर 9 लाख 93 हजार की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों नैना, राहुल उपाध्याय एवं राजीव सिंह को पुलिस व साइबर सेल की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे लैपटॉप, मोबाईल पेनकार्ड, आधार कार्ड, एटीएम, पासबुक व हार्डडिस्क बरामद हुआ हैं। पकड़े गए आरोपी बीजापुर के अलावा मनेन्द्रगढ़ व गरियाबंद में भी सायबर ठगी के मामले में नामजद आरोपी हैं। अब तक आरोपियों के विरुद्ध लगभग 50 लाख के फ्राड के मामला सामने आए हैं।

बीजापुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर के तहसील पारा निवासी कौशिक मोरला ने बीजापुर थाना में 15 दिसंबर 2022 को एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पास एक कॉल आया जो अपना नाम अंजली शर्मा बताई। उसने सेबी कार्यालय हैदराबाद से बात करने की बात कही। उसने कहा कि आपके पॉलिसी पैसा वापस नहीं मिला है तो शिकायत दर्ज कराने एवं पैसे वापस दिलाने की बात कहते हुए शिकायत दर्ज कराने कहा। प्रार्थी ने वर्ष 2012 में साई प्रसाद कंपनी से ली गई पॉलिसी की राशि नहीं मिलने से उक्त राशि वापस दिलाने शिकायत इन्हें

बताया गया। इसके बाद दूसरे नंबर से मधुकर राव नाम बताकर अपने आपको सेबी अधिकारी बताते हुए लिखित शिकायत, आधार कार्ड, पॉलिसी नंबर व दस्तावेज मेल पर उपलब्ध कराने कहा गया। शिकायत के बाद मधुकर राव द्वारा प्रार्थी को सेबी में शिकायत दर्ज कराने का शिकायत नंबर दिया गया। मधुकर राव द्वारा प्रोसेसिंग फीस, वकील की फीस आदि बता कर अब तक 9,93,000/- राशि की ठगी कर ली गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर बीजापुर थाना में धारा 420, 34 भादवि की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद एसपी, एएसपी के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार के दिशा निर्देश में 5 जून 2023 को बीजापुर थाना व सायबर सेल की टीम आरोपियों की पतासाजी व गिरफ्तारी के लिए सायबर सेल से तकनीकी सहायता से दिल्ली व गाजियाबाद के लिए रवाना हुई। आरोपियों के खाता व सिम के एड्रेस पर पतासाजी की गई, जो पता फर्जी पाया गया।

चीतल का अवैध शिकार 10 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी। केरेगांव वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कांटाकुरीडीह क्षेत्र में वन्य प्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार करने वाले 10 आरोपियों को केरेगांव रेंज वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। इनके पास से वन विभाग की टीम ने 3 धनुष व 4 तीर जब्त किए गए।

उल्लेखनीय है कि जंगल क्षेत्र में चीतल, सांभर एवं अन्य वन्य प्राणी पास के गांव की ओर विचरण करने पहुंचते हैं जिसका कुछ ग्रामीण शिकार कर इसका फायठा उठाते है। ऐसे ही कांटाकुरीडीह के स्कूल परिसर के पास पहुंचे शीतल का 10 ग्रामीणों ने शिकार किया। इसकी सूचना मिलते ही सर्च वारंट जारी कर डीएफओ धमतरी मयंक पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं एसडीओ धमतरी टीआर वर्मा के निर्देशन में परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव के नेतृत्व में भरत लाल वर्मा एवं इनकी टीम पंचराम साहू परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर, उत्पादन डिप्टी रेंजर उत्तर सिंगपुर ओंकार सिन्हा, डिप्टी रेंजर केरेंगांव पुरूषोत्तम पाण्डेय, नरेश उपाध्यक्ष डिप्टी रेंजर उडनदस्ता प्रभारी, परिक्षेत्र सहायक मंशाराम साहू, बीएफओ कुकरेल दुलेश्वर मार्कण्डेय, कुलेश्वर बघेल महिला वनरक्षक एवं स्टाफ परिक्षेत्र केरेगांव ने वन्य प्राणी चीतल के अवैध शिकार के 10 आरोपियों को सर्चिंग कर पकड़ा, जिन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों से 3 धनुष, 4 तीर जब्त किए गए।

आरोपियों में जोहर सिंग कमार (33 वर्ष), भुवन कमार (35 वर्ष), बीरेंद्र कमार (24 वर्ष), पुराणिक कमार (28 वर्ष), मनीराम कमार (25 वर्ष), राधे लाल कमार (18 वर्ष), चैत राम कमार (30 वर्ष), आनंद कमार (19 वर्ष), किशन कमार (25 वर्ष) और दुर्गेश कमार (19 वर्ष) सभी ग्राम बरबान्धा (बगबुडा पारा) पर पीओआर क्रमांक 1487 / 13 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, व 50 एवं 51, 52 के तहत कार्रवाई की गई।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

किसान सम्मान निधि वापस करने का फरमान किसान विरोधी चेहरा है : कश्यप

जगदलपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि प्रदेश की भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से किसान सम्मान निधि की राशि वापस मांग रही है, जिसके कारण किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि प्रदेश की भूपेश बघेल को सरकार ने सत्ता में आने के लिए ढेर सारे वादे किए पर सरकार बनाने के बाद वह अपने वादों से मुकर रही है। कश्यप ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसान सम्मान निधि के नाम पर भारी भ्रष्टाचार कर रही है, सरकार किसानों से सम्मान निधि के राशि वापस मांग रही है, जो शर्मनाक है और किसान भाइयों के साथ सरासर विश्वासघात है। उन्होने कहा कि राज्य सरकार को गलती का खामियाजा किसान क्यों भुगते? इस मामले में सरकार पूरी जांच करवाए और स्थिति स्पष्ट करे, ताकि किसान भाइयों के समक्ष संकट की स्थिति निर्मित न हो।

छत्तीसगढ़ से लखनऊ जा रही एसी बस पलटी, 20 घायल

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में लखनऊ जा रही तेज रफ्तार एसी बस मंगलवार देर शाम अनियंत्रित होकर पलट गई। इसके चलते बस में सवार महिलाओं और बच्चों सहित 20 यात्री घायल हो गए हैं। हादसे में घायल एक बच्चे की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की सहायता से बस का शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन हाईवे के चलते बस स्लिप होकर खेत में जा गिरी थी। हादसा पांडातराई थाना क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक, कबीरधाम से एसी बस यात्रियों को लेकर लखनऊ के लिए निकली थी। अभी बस ग्राम परसवारा के पास मुख्य मार्ग से पोड़ी-पंडरिया नेशनल हाईवे पर पहुंची थी कि अनियंत्रित होकर पलट गई। रफ्तार तेज होने के चलते बस फिसलते हुए खेत में जा गिरी। इसके बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों और राहगीरों ने हादसा होते देखा तो बस के आगे का शीशा तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

रिसाली आयुक्त से अवैध कब्जा हटाने की मांग की

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली के अन्तर्गत आने वाले रुआबांधा साप्ताहिक सब्जी बाजार में विद्यालय के पास अवैध कब्जा हटाने की मांग नागरिको ने की है। आयुक्त को सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा गया है कि रिसाली नगर पालिक निगम अन्तर्गत आने वाले रुआबांधा में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार स्थित विद्यालय के पास में कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रुप से ठेला एवं बांस-बल्ली तिरपाल डालकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। जिससे वहाँ सब्जी का व्यवसाय करने वालों की दुकानें लगाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।अवैध कब्जाधारियों को देखते हुए अन्य लोग भी उपरोक्त स्थल पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये रुआवांधा सब्जी बाजार में किये जा रहे अवैध कब्जो को तत्काल प्रभाव से हटवाने की कृपा करें ।ताकि उपरोक्त स्थल पर व्यसाय कर रहे व्यवसायियों को सुविधा प्राप्त हो सके एवं उनकी रोजी-रोटी चल सके ।यह जानकारी अवधेश सिंह अध्यक्ष ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताई।

रेलवे स्टेशन तक पहुंची खेतों में लगी आग

बालोद। बालोद जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के पास स्थित रेलवे के स्टोर रूम के खुले मैदान में रखे सामान जलकर खाक हो गए।

दरअसल खेतों की सफाई के दौरान कचरा जलाने के आग लगाई गई थी। शाम होते होते यह आग खेतों से रेलवे यार्ड तक पहुंची और और आग तेजी से फैल गई। आग की लपटों में रेलवे के कई सामान जलकर खाक हो गए। आनन-फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाने में काफी देर हो गई और करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। रेलवे विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार आज देर शाम को लगी थी और बुझाते बुझाते रात हो गई सुबह जब नुकसान का अंदेशा लगाया गया तो लगभग डेढ़ करोड़ के सामान जलने की बात सामने आई। फिलहाल बाहर से टीम आकर इसकी जांच करेगी। रेलवे और पुलिस में भी इसकी सूचना दे दी गई है। आगे जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

पहले से बेहतर जीत के लिए अल्पसंख्यक विभाग मुस्तैद

दुर्ग। जिला कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के सक्रिय कार्यकर्ता युवा समाजसेवी शेख साबिर ने राजीव भवन रायपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रदेश प्रभारी निजामुद्दीन राइन एवं सह प्रभारी आसिफपाशा के प्रथम आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष अमीन मेमन के नेतृत्व मे उनसे मुलाकात कर दिली इस्तकबाल किया एवं अल्पसंख्यक विभाग प्रभारी, सहप्रभारी व प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष को खूबसूरत बस्तर आर्ट भेंट कर बस्तर के सौंदर्य, कांग्रेस सरकार द्वारा बस्तर की तस्वीर बदलकर अमन और विकास के बारे में बताते हुए कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ बस्तर में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के प्रति जो भरोसा कायम है, वह फिर से पिछली कामयाबी को बरकरार रखने का सबब बनेगा। शेख साबिर ने आगामी विधनसभा चुनाव के बारे में चर्चा करते हुए अल्पसंख्यक विभाग के प्रभारी, सह प्रभारी को विश्वास दिलाया कि चुनाव में कांग्रेस दुर्ग संभाग की सभी सीटों पर कांग्रेस परचम लहराने को तैयार है।

भाजपा ने शहर को गंदगी से मुक्त करवाने सेल्फी विथ कचरा अभियान चलाया

महापौर ने कहा कि शहर की सफाई नही होने का आरोप लगाना सरासर गलत

जगदलपुर। जिला मुख्यालय में निगम क्षेत्र अंर्तगम भाजपा के नेता और पार्षदों ने शहर को गंदगी से मुक्त करवाने सेल्फी विथ कचरा अभियान चलाया है, यह अभियान बुधवार को भी जारी रहा। जिसके तहत भाजपा के नेता और पार्षद नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में पसरी गंदगी और कूड़े के ढेर के साथ अपनी सेल्फी ले रहे हैं, जिसे सोशल मीडिया में पोस्ट किया जा रहा है। इनका मानना है कि ऐसा करने पर लोग जागरूक भी होंगे और निगम सफाई के लिए मजबूर होगी।

भाजपाइयों पार्षदों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के दलपत सागर वार्ड, मोतीलाल वार्ड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड समेत अन्य वार्डों से कचरा का उठाव नहीं हुआ है। निगम के सफाई कर्मचारी वार्डों में नहीं पहुंच रहे हैं।

गंदगी और बदबू से शहर के लोग काफी परेशान हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम विफल है इसलिए भाजपा ने कचरा के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया में अभियान चलाने की मुहिम छेड़ी है। जिसके तहत करीब 12 से ज्यादा वार्ड के पार्षद और लोगों ने सेल्फी लेकर नगर निगम को अल्टीमेटम भी दिया गया है।

भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम की कांग्रेस महापौर सफीरा साहू को शहर की चिंता नहीं है। वे अपने में मस्त हैं, पूरे शहर में गंदगी का आलम है। कई दिनों से कचरा साफ नहीं किया जा रहा है। लोग बदबू से त्रस्त हैं। इसलिए हमने सोशल मीडिया में इस तरह की मुहिम चलाने का सोचा। अब यदि व्यवस्था नहीं सुधरती है तो सारे वार्डों का कचरा लेकर हम नगर निगम जाएंगे और वहां धरना देंगे।

जगदलपुर नगर निगम की महापौर सफीरा साहू ने कहा कि शहर की सफाई नही होने का आरोप लगाना सरासर गलत है। अभी मानसून से पूर्व शहर की सारी नालियों की सफाई की जा रही है। जब नाली साफ करते हैं तो कचरा गीला रहता है। इसलिए उसी जगह पर छोड़ा जाता है। ठीक अगले दिन सुबह सफाई कर्मी पहुंचकर कचरा को उठा लेते हैं। भाजपा के लोगों के पास और कोई काम नहीं है, इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं।

संकट में सरोवर पर वार्डवासियों का फूटा गुस्सा, सड़कों पर उतरकर जताया विरोध

कांकेर। जल संरक्षण के लिए जिले में तमाम प्रयास किये जा रहे हैं। बावजूद इसके आज भी शहर के लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। पुराने समय से नगर के लोग तालाबों पर ही निर्भर हैं। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब इन तालाबों का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है। जिससे नाराज दो वार्ड के लोग बुधवार को कांकेर कलेक्टर के पास फरियाद लेकर पहुंचे। टिकरापारा और अघन नगर के वार्डवासियों का कहना है कि दुधावा तालाब और बैजनाथ तालाब की स्थिति बेहद दयनीय है। यहां लोगों को निस्तारी के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है।

वार्डवासी घनेद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि दुधावा तालाब शहर का प्रमुख तालाब है, जहां लंबे समय से गहरीकरण तक नहीं किया गया है। पानी की जगह अब केवल दलदल बचा हुआ है। देवी देवताओं के जोत ज्वारा के विसर्जन के साथ ही साथ नवरात्र और गणेश चतुर्थी पर्व में मूर्तियों का विसर्जन यहीं होता है। जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के बहुत से परिजन भी इस तालाब का उपयोग करते हैं। पूजा पाठ जैसे सांस्कृतिक महत्वों और अन्य कार्यो के लिए भी इस तालाब का उपयोग किया जाता है। पहाड़ से लगे होने के कारण जंगली जानवर और आवारा मवेशी भी इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। यही तीन वार्ड के लोगों के लिए निस्तारी का एक मात्र जरिया है।

वार्डवासी इंदु नेताम ने बताया कि बैजनाथ तालाब को कुछ साल पहले गहरीकरण कर छोड़ दिया गया। लेकिन वहां बारिश का पानी जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब दोनों तालाबों में निस्तारी के लिए पानी नहीं है, जिससे वार्डवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वार्डवासियों की मांग है कि यदि दुधावा तालाब और बैजनाथ तालाब का गहरीकरण और सौंदर्यीकरण नहीं किया जाता है तो, वार्डवासी उग्र आंदोलन करेंगे। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अमित शाह ने रद्द किया तेलंगाना दौरा

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया गया है। अमित शाह खुद चक्रवात की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। गुजरात पर बिपारजॉय चक्रवात का प्रभाव अधिक है। इस वजह से उनका तेलंगाना दौरा रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि चक्रवात बिपारजॉय के कारण अमित शाह की स्थिति की समीक्षा करने की आवश्यकता के कारण उनकीकी तेलंगाना यात्रा रद्द कर दी गई है। माना जा रहा है कि अमित शाह खुद गुजरात के लिए रवाना हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 17 जून को होने वाली ओडिशा यात्रा को चक्रवात बिपारजॉय के कारण हुई असाधारण स्थिति के मद्देनजर रोक दिया गया है। भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा करते हुए, राज्य भाजपा महासचिव पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि केंद्र सरकार चक्रवात बिपारजॉय से उत्पन्न स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है।

सरकार प्रतिशोध की राजनीति कर रही, झुकेंगे नहीं : खड़गे

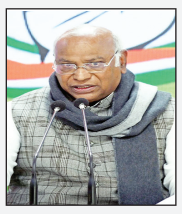

नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कदम को सरकार द्वारा उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति करार देते हुए बुधवार को कहा कि विपक्षी दल ऐसी कार्रवाइयों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। खरगे ने एक बयान में कहा, यह (बालाजी के खिलाफ कार्रवाई) कुछ और नहीं, बल्कि मोदी सरकार द्वारा उन लोगों के खिलाफ राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध की कार्रवाई है, जो उसका विरोध करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने जोर देकर कहा, विपक्ष में कोई भी ऐसे कदमों के सामने झुकने वाला नहीं है। गौरतलब है कि ईडी ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे। बाद में बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया।

नीतीश ने कहा कि पार्टी में आ जाएं या फिर बाहर चले जाएं

पटना। बिहार मे नीतीश सरकार से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बेटे के इस्तीफे के बाद पहली बार जीतन राम मांक्षी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से व्यक्तिगत परेशानी नहीं है लेकिन जनहित के साथ समझौता नहीं होगा। मांझी ने कहा कि हमने अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष रहा लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी में आ जाएं या फिर बाहर चले जाएं। मांझी के बेटे का इस्तीफा नीतीश कुमार के लिए विपक्षी एकता की बैठक से पहले बड़ी झटका माना जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी कुछ मांगे थी, हम लगातार अपनी मांग रखते रहे। किसानों को बिजली मुफ्त में देने की बात थी। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की बात थी। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। उन्होंने कहा कि हम कुछ बातों को इंप्लीमेंट कराना चाहते थे जिससे कि बिहार का भविष्य बदल सकता था। लेकिन उसे नहीं माना गया।

कांग्रेस कर्नाटक से लोकसभा में 20 सीटें जीतेगी : सिद्धारमैया

बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अकेले कर्नाटक में 20 सीटें जीतने का दावा किया गया है। जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा ने बीते मंगलवार को कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में एक भी वोट नहीं मिलेगा और सूबे की सारी सीटें भाजपा को मिलेंगी। सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि सिद्धारमैया भारी मुगालते में हैं, विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नहीं बल्कि उसके द्वारा किये वादों को दिया है। इसके साथ ही भाजपा सांसद सिम्हा ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता कांग्रेस को नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देगी ताकि वो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा, भाजपा की लहर 2014 में भी थी, 2019 में भी थी और 2024 में भी मोदी की लहर रहेगी और यह बात में केवल कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कह रहा हूं।

नीतीश कैबिनेट का 16 जून को होगा विस्तार

पटना। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार 16 जून को किया जाएगा। 16 जून की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। जनता दल यूनाइटेड कोटे से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसे लेकर राज्यपाल सचिवालय, बिहार की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है। अबतक राजद और कांग्रेस के नाम सामने नहीं आए हैं, जिसके कारण कांग्रेस की नाराजगी किसी भी रूप में कभी भी सामने आ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात कई बार उठकर दब चुकी है, लेकिन इस बार जब जनता दल यूनाईटेड के खाते से हिन्दुस्तानी आवामी मोर्चा (हम) के इकलौते मंत्री संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी ने इस्तीफा दिया तो जदयू ने आपदा प्रबंधन के तहत न केवल मंत्रीपद के लिए नाम फाइनल किया, बल्कि मुख्यमंत्री की ओर से मनोनयन के बाद राज्यपाल की ओर से शपथ ग्रहण की चिट्ठी भी जारी कर दी गई।

अमित शाह ने कहा- व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ

भारत एफडीआई के लिए पहली पसंद बना

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने नौ साल पूरे कर लिए हैं, जिसे भाजपा नेता जश्न के रूप में मना रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत इन नौ सालों में लाल फीता शाही से रेड कार्पेट तक का सफर तय किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने परेशानियों को दूर करके व्यापार के लिए एक बेहतर माहौल तैयार किया है। मोदी सरकार के कारण भारत एफडीआई के लिए पहली पसंद बन चुका है। पीएम मोदी के नेतृत्व में अब व्यापार करना आसान हो गया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेहतर टैक्स पॉलिसी लागू की गई है। निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। बिना परेशानी के सुगम व्यापार करने के लिए माहौल तैयार किया है। भारत को एफडीआई के लिए पहली पसंद बनाया गया। शाह ने कहा कि स्टार्ट अप इंडिया हो या स्टैंड अप इंडिया हो या फिर पीएलआई या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भाजपा सरकार ने हमेशा विकास, बढ़त और नवाचारों को बढ़ावा

दिया है।

अमित शाह 23 जून को जम्मू में जनसभा को संबोधित करेंगे :भाजपा

जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 जून को डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जम्मू-कश्मीर इकाई के अध्यक्ष रविंदर रैना ने यह जानकारी दी। भाजपा 23 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। रविंदर रैना ने कहा, '' जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू संसदीय क्षेत्र में 23 जून को जम्मू शहर में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। ''

रविंदर रैना ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए आयोजित एक महा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को रैलियों में शामिल होने के लिए जनता को लामबंद करने के लिए अधिक समय देना होगा, जिसमें अमित शाह की एक रैली भी शामिल है। जम्मू-कश्मीर भाजपा के महासचिव (संगठन) अशोक कौल ने कहा कि महा जनसंपर्क अभियान को जनता से भारी समर्थन मिला है और जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है।

पवार की अगुवाई में विपक्ष 2024 के आम चुनाव के लिए जुटा

जल्द बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम

दिल्ली। विपक्षी दल शरद पवार की अगुवाई में 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए तैयार कर रहे हैं। खबरों के अनुसार 23 जून को पटना में होने वाली गैर-भाजपा विपक्षी दलों की पहली बैठक से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार के नेतृत्व में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति बनाने के लिए आरंभिक चर्चा शुरू हो गई है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक की मेजबानी करने वाला है। इसी क्रम में विपक्षी दलों का अगले साल होने वाले आम चुनाव में संयुक्त एजेंडा क्या हो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) क्या हो। इसे बनाने के लिए विपक्ष शरद पावर के नेतृत्व में काम कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार विपक्ष के एक नेता ने कहा, नीतीश कुमार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि वह पीएम उम्मीदवार नहीं हैं। वह विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण से विपक्षी दलों की आपसी रजामंदी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम

सहित अन्य मुद्दों पर स्वीकार्य फैसला लेने के लिए विभिन्न समितियों के गठन का प्रयास कर रहा है।

विपक्षी दलों ने शरद पवार के लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव और राजनीतिक कौशल को देखते हुए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) बनाने की जिम्मेदारी उन्हें दे सका है। मराठा जनमत पर खासा प्रभाव रखने वाले शरद पवार ने साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा विरोधी महाविकास अघाड़ी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए थे।

तमिलनाडु में जांच के लिए सीबीआई को लेनी होगी राज्य सरकार की अनुमति

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सीबीआई को अब तक दी जा रही सामान्य सहमति वापस ले ली है। अब सीबीआई को राज्य में जांच से पहले तमिलनाडु सरकार की इजाजत लेनी होगी। इससे पहले पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब और तेलंगाना में भी यह लागू है। तमिलनाडु गृह विभाग द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम,1946 (1946 का केंद्रीय अधिनियम 25) के एक विशेष प्रावधान के अनुसार सीबीआई को जांच करने के लिए जाने से पहले संबद्ध राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। आदेश में कहा गया कि तमिलनाडु सरकार ने उक्त नियम के तहत 1989 और 1992 में कुछ तरह के मामलों में दी गई सहमति वापस लेने का आज आदेश जारी किया है। इस तरह सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। माना जा रहा है कि तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद राज्य सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राज्य सरकार का फैसला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) पर लागू नहीं होता। सेंथिल बालाजी को ईडी ने परिवहन विभाग में नौकरियों के बदले नकदी घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है।

सरकार की बैठकों में शामिल हो रहे सुरजेवाला: भाजपा

बेंगलुरु। कर्नाटक में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को कुछ अधिकारियों के साथ उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में भाग लेने के बाद सत्तारूढ़ कांग्रेस पर हमला किया। भगवा पार्टी ने सुरजेवाला से सवाल किया कि उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक में भाग क्यों लिया, जिसमें बेंगलुरु नागरिक निकाय, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके के अधिकारी शामिल थे। बैठक का आयोजन एक निजी होटल में किया गया था। कर्नाटक के भाजपा विधायक आर अशोक ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला बैठक कर रहे हैं। वह बैठक चला रहे हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वे कर्नाटक को बीबीएमपी बनाना चाहते हैं, एक एटीएम टू कांग्रेस। वे सीधे 10 जनपथ से एटीएम के लिए आए थे। इसलिए हमने राज्यपाल से शिकायत की। उन्होंने हमारा पत्र लिया है, वे पूछताछ करेंगे और सरकार और मुख्य सचिव को दिशा-निर्देश देंगे। कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि एआईसीसी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कोई बैठक नहीं ली है। मंत्री, डिप्टी सीएम होटल में बैठक कर रहे थे और महासचिव उस होटल में थे। पीसीसी अध्यक्ष उनसे बात करना चाहते थे। वह उन्हें बुलाया और वह बस आकर पीसीसी अध्यक्ष के साथ बैठ गए। उस समय 2-3 अधिकारी थे, वे मंत्री के साथ चर्चा करने आए थे। महासचिव ने कभी अधिकारियों के साथ बैठक नहीं की।

जम्मू-कश्मीर में 6-7 साल तक चुनाव नहीं हुए, फिर भी एक भी पार्टी नहीं उठा रही सवाल: गुलाम नबी आजाद

श्रीनगर। देश में राजनीति एकता की कवायद जोर-शोर से उठ रही है और मोदी सरकार के विरूद्ध महागठबंधन बनाने की कोशिशें भी आकर ले रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर के नेता इससे खासा इत्तेफाक रखते नहीं नजर आ रहे हैं। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने और फिर अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस पहल को ज्यादा तव्जयों नहीं दिया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में छह साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं और एक भी पार्टी इस पर सवाल नहीं उठा रही है। इसलिए, उमर अब्दुल्ला जो कह रहे हैं वह सही है। मुझे दूसरी राजनीतिक पार्टियों से भी यही शिकायत है। जब उनकी बात आती है तो वे एकता की बात करते हैं और जब यहां 6-7 साल तक चुनाव नहीं होते हैं तो एक भी पार्टी आवाज नहीं उठाती है। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने से डर रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनसे खुश नहीं है। मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोग खुश और संतुष्ट होते तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने (केंद्र) यहां चुनावों की घोषणा की होती।

खेल
प्रमुख समाचार

इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच 16 जून से एशेज सीरीज का आगाज

एजबेस्टन । विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम फॉर्म में है। एशेज सीरीज का पहला टेस्ट 16 जून से खेला जाना है। डब्ल्यूटीसी फाइनल को एशेज की तैयारी के लिए अहम माना जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के फाइनल जीतने के बाद इंग्लैंड को कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता में से एक की शुरुआत हो रही है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एशेज सीरीज में एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम आत्मविश्वास से भरी होगी। दूसरी ओर इंग्लैंड ने इस महीने की शुरुआत में आयरलैंड को रौंद दिया था।

ऑस्ट्रेलियाई टीम- पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कारी , कैमरन ग्रीन, मार्कस हैरिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिशेल मार्श, टॉड मरफी, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, डेविड वॉर्नर।

इंग्लैंड की टीम-बेन स्टोक्स (कप्तान), मोईन अली, जेम्स एंडरसन, जोनाथन बेयरस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड, हैरी ब्रूक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, ओली पोप, मैथ्यू पॉट्स, ओली रॉबिन्सन, जो रूट, जोश टोंग, क्रिस वोक्स और मार्क वुड।

इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज

पहला टेस्ट: 16 जून से 20 जून, समय- स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे, एजबेस्टन, बर्मिंघम। दूसरा टेस्ट: 28 जून से 2 जुलाई, समय- सुबह 11 बजे स्थानीय समय, लॉर्ड्स, लंदन। तीसरा टेस्ट: 6 जुलाई से 10 जुलाई, समय- स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे, हेडिंग्ले, लीड्स। चौथा टेस्ट: 19 जुलाई से 23 जुलाई, समय- 11 पूर्वाह्न स्थानीय समय, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर। पांचवां टेस्ट: 27 जुलाई से 31 जुलाई, समय- स्थानीय समयानुसार सुबह 11 बजे, केनिंग्टन ओवल, लंदन।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 85 अंक मजबूत निफ्टी 18,750 के पार

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 85 अंक मजबूत हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 40 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,755.90 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 85.35 अंक यानी 0.14 फीसदी की बढ़त के साथ 63,228.51 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 63,274.03 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 63,013.51 तक आया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 39.75 अंक यानी 0.21 फीसदी की तेजी देखी गई। निफ्टी कारोबार के अंत में 18,755.90 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,769.70 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,690.00 तक आया।

तीन साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंची थोक महंगाई

नईदिल्ली। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मई में घटकर शून्य से 3.48 प्रतिशत नीचे आ गई है। यह इसका तीन साल का निचला स्तर है। मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, ईंधन और विनिर्मित वस्तुओं के दाम घटने से थोक मुद्रास्फीति नीचे आई है। यह लगातार दूसरा महीना है जबकि थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति शून्य से नीचे है। अप्रैल में यह (-) 0.92 प्रतिशत पर थी। मई, 2022 में थोक मुद्रास्फीति 16.63 प्रतिशत पर थी। मई, 2023 का मुद्रास्फीति का आंकड़ा तीन साल का निचला स्तर है। इससे पहले मई, 2020 में थोक मुद्रास्फीति (-) 3.37 प्रतिशत पर थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति घटकर 1.51 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल में यह 3.54 प्रतिशत पर थी। ईंधन और बिजली खंड की मुद्रास्फीति मई में घटकर (-) 9.17 प्रतिशत पर आ गई। अप्रैल में यह 0.93 प्रतिशत थी।

वोडाफोन आइडिया ने बिजनेस रिवाइवल के लिए 14000 करोड़ की इक्विटी का रखा प्रस्ताव

नईदिल्ली। कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया ने अपना कारोबार वापस पटरी पर लाने के लिए एक बड़ा निवेश का प्रस्ताव रखा है। खबरों के मुताबिक, कंपनी अपने बिजनेस रिवाइवल के लिए 14000 करोड़ रुपये की इक्विटी लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक खबर के मुताबिक, मौजूदा प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और यूके का वोडाफोन ग्रुप पीएलसी कुल राशी का आधा हिस्सा लगाएंगे। बता दें कि इस खबर के आने के बाद ही कंपनी के स्टॉक्स में तेजी दर्झ हुई। शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 10 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली। इस महीने की शुरुआत में सरकार को सौंपी गई योजना के अनुसार, एबीजी और वोडाफोन ग्रुप जल्द ही कंपनी में नई इक्विटी के रूप में रू. 2,000 करोड़ का निवेश करेंगे।

ऐपल का भारत में 2025 तक 18% आईफोन होंगे देसी!

नईदिल्ली। ऐपल भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ा रही है। मोबाइल फोन के लिए केंद्र की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत, टेक दिग्गज ऐपल की योजना वित्त वर्ष 2025 तक ग्लोबल आईफोन के प्रोडक्शन का 18 फीसदी भारत में शिफ्ट करने की है। बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। बता दें कि वित्त वर्ष 2023 में, आईफोन के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी 7 फीसदी थी। पीएलआई योजना के आने से पहले आईफोन के ग्लोबल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी नगण्य थी। पीएलआई योजना को पहली बार 6 अक्टूबर, 2020 को अधिसूचित किया गया था। 2020 में ही, केंद्र सरकार ने फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन को मंजूरी दी, जो सभी भारत में ऐपल के अनुबंध निर्माता हैं।

क्रिप्टो करंसी के भंवर में फंसा अमेरिका

बिक्रम उपाध्याय

अमेरिकी बाजार पर इन दिनों ग्रहण लगा हुआ है। बैंक और शेयर बाजार में आए एक बड़े भूचाल से अमेरिका संभला ही था कि अब क्रिप्टो संकट में फंस गया है। इन दिनों अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) एक साथ कई मामलों की जांच कर रहा है, जिनमें पिछले हफ्ते क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस और कॉइन बेस के जरिए 4 अरब डॉलर निकाल ले जाने की भी जांच शामिल है। इस गड़बडी की जद में अमेरिका की कई वेंचर कैपिटल फर्म भी आ सकती हैं जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक कुछ महीने पहले आया था और यह बैंक दिवालिया होने के बाद बिक गया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस कहीं उसी दशा को तो प्राप्त नहीं हो जाएगा, जिस दशा में अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेज एफटीएक्स पहुंच गया था। 11 नवंबर, 2022 को एफटीएक्स ने अचानक दिवालियापन के लिए अपील दायर कर दी थी। एक अमेरिकी एजेंसी के अनुसार एफटीएक्स में निवेशकों के 9 अरब डॉलर डूब गए थे। बाद में एफटीएक्स के पूर्व संस्थापक और सीईओ सैम बैंकमैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाइनेंस भी क्रिप्टो एक्सचेंज ही है और एसईसी की जांच के बाद से इस एक्सचेंज के जरिए अभी तक 4 अरब डॉलर निकाले जा चुके हैं।

अमेरिकी क्रिप्टो बाजार में घोटाले का धुंआ जब-जब उठता है पूरी दुनिया के निवेशकों के हाथ जल जाते हैं। कारण बिटकॉइन, इथीरियम और कुछ अन्य क्रिप्टो में भारत समेत पूरी दुनिया का पैसा लगा है और उनके धराशायी होने का मतलब पूरी दुनिया की पूंजी डूबना हो सकता है।

अमेरिकी बैंकों में पहले से ही न केवल ठहराव का भय व्याप्त है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र में गिरावट ही देखी जा रही है। ऐसे में अमेरिकी निवेशकों को क्रिप्टो बाजार से एक उम्मीद बंधी थी पर वहां भी लगातार घोटालों की खबर से निवेशकों का विश्वास डोल गया है। एफटीएक्स के दिवालियापन और बाइनेंस के साथ नए विवाद ने ना केवल बाजार में भारी बिकवाली शुरू कर दी है, बल्कि क्रिप्टो बाजार से तरलता भी कम कर दी है। 6 जून को बिटकॉइन में 4 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।

दरअसल पूरा क्रिप्टो बाजार ही मैन्यूपुलेशन का खेल बन गया है और इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में अमेरिकी नेशनल फुटबॉल लीग मिनेसोटा वाइकिंग्स के पूर्व सह स्वामी रेजिनाल्ड फाउलर को छह साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई और अमेरिकी अदालत द्वारा उनके 740 मिलियन डॉलर जब्त करने का आदेश दिया गया। क्रिप्टो की दुनिया में संभवत फाउलर पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें क्रिप्टो घोटाले का दोषी मानकर इतनी बड़ी सजा दी गई है। फाउलर पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के जरिए मनी-लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। फाउलर क्रिप्टो घोटाले में शामिल अकेले प्रमुख व्यक्ति नहीं है। बल्कि हर चौथी करेंसी के साथ किसी न किसी घोटालेबाज का नाम जुड़ा हुआ है। फाउलर से पहले टेसला के सीईओ एलोन मस्क के खिलाफ भी क्रिप्टो बाजार में हेरफेर का मुकदमा दायर किया जा चुका है। उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग और लोकप्रिय मीम क्रिप्टोकरेंसी डॉजकॉइन के बाजार में हेरफेर का आरोप है। मस्क पर आरोप लगाने वालों का कहना है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्विटर का उपयोग क्रिप्टो करेंसी बाजार को मैनिपुलेट करने में किया। न्यूयॉर्क के अमेरिकी दक्षिणी जिला न्यायालय में 31 मई को दायर एक संशोधित फाइल में कहा गया है कि मस्क ने डॉजकोइन क्रिप्टोकरेंसी के लिए बाजार में बेतहाशा हेरफेर किया। मस्क ने ट्विटर पोस्ट और कमेंट के जरिए डॉजक्राइन को बढ़ावा दिया और कीमतों में उतार-चढ़ाव से जबर्दस्त मुनाफा कमाया, जबकि खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। क्रिप्टो बाजार में हेराफेरी के कारण सिलिकॉन वैली बैंक 2023 में विफल होने वाला पहला ऋणदाता था, इसके बाद सिल्वरगेट बैंक और सिग्नेचर बैंक में भी क्रिप्टो के झटके आ रहे हैं।

मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा की रणनीति

अभय कुमार दुबे

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों में मुसलमानों को भी टिकट दिया। पचास-पचपन मुसलमान उम्मीदवार जीते भी। दरअसल, भाजपा के रणनीतिकारों के लिए ये दो अलग-अलग बातें हैं। कर्नाटक में उनके सामने समस्या यह थी कि हिंदुओं की गोलबंदी का प्रतिशत कैसे बढ़ाएं यानी लिंगायतों को प्रसन्न रखते हुए वोक्कलिगाओं को अपने साथ कैसे जोड़ें। इसके उलट उत्तर प्रदेश में वे मुसलमानों को टिकट देने का प्रयोग करने की तरफ गए क्योंकि वहां हिंदू गोलबंदी पहले से ही अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वह मुसलमानों को भविष्य के मतदाता के रूप में देख रही है। वक्त के साथ भाजपा की यह मुसलमान-रणनीति और भी परवान चढ़ सकती है। भाजपा पिछले दो साल से एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिसके इच्छित परिणाम अगर निकले तो वह आने वाले समय में अपने वोटों का राष्ट्रीय प्रतिशत चालीस या उसके पार पहुंचा सकती है। इस समय भाजपा ज्यादा से ज्यादा 37-38 फीसदी वोटों की पार्टी है। विपक्षी मतों के बंटवारे के कारण उसे एक मजबूत बहुमत की सरकार बनाने का मौका अवश्य मिल गया है, लेकिन अगर कांग्रेस के अच्छे जमानों से तुलना की जाए तो यह पार्टी दो चुनाव जीतने के बावजूद 45 फीसदी वोट पाने के आंकड़े से काफी पीछे नजर आती है। यह रणनीति मुसलमान वोटों को अपनी ओर खींचने की है। इसके लिए भाजपा की निगाह पसमांदा मुसलमानों पर है जो व्यावहारिक रूप से मुस्लिम समाज की तकरीबन अस्सी प्रतिशत आबादी बनाते हैं। मेहनतकश, गरीब और कारीगर जातियों की इस मुसलमान जनता का राजनीतिक नेतृत्व आजादी के पहले से ही ऊंची जातियों के संपन्न और कुलीन समझे जाने वाले अशराफ नेतृत्व को चुनौती देता रहा है। एक प्रतिष्ठित समीक्षक के अनुसार पसमांदा वोटरों के भाजपा की तरफ रुझान से पार्टी को डेढ़ से ढाई फीसदी वोटों का लाभ मिल सकता है जिससे वह चालीस फीसदी की रेंज में पहुंच सकती है। दूसरे, इससे हिंदू वोटरों की गोलबंदी में निहित समस्याओं का सामना करने में भी मदद मिलेगी। यह सही है कि भाजपा को ओबीसी और दलित वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा उस तरह पक्की नहीं है जिस तरह ऊंची जातियों की है। ये वोटर कभी-कभी पार्टी का साथ छोड़ भी देते हैं। इससे पैदा हुए संकट का सामना करने में भी भाजपा की मदद पसमांदा वोटर कर सकते हैं। भाजपा की दूसरी रणनीति का ताल्लुक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से है। इस परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बाद उसे नहीं रोका जा सकेगा। भाजपा चाहे तो परिसीमन के जरिये अपने प्रभाव-क्षेत्र की सीटें बढ़ा सकती है, और उनके इलाकों की सीटें कम कर सकती है जहां उसे समर्थन या तो कम मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता। मसलन, परिसीमन के परिणामस्वरूप हिंदी क्षेत्र की 33 सीटें बढ़ सकती हैं और इसका खामियाजा दक्षिण भारत को उठाना पड़ सकता है वहां की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। यह सब करने के लिए भाजपा को किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना है। ऐसा करने के लिए उसे केवल आबादी के मुताबिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू करना होगा। यह अलग बात है कि इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने आबादी पर नियंत्रण करने के सफल और प्रशंसनीय उपाय किए। परिसीमन के भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या नतीजे निकलेंगे, इसका पूरा तथ्यात्मक अनुमान अभी नहीं लगाया गया है। नई संसद में लोकसभा सदस्यों की लगभग दोगुनी संख्या बैठ सकती है। अगर दक्षिण की मौजूदा सीटें कायम रखनी हैं, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या आठ सौ से ज्यादा करनी होगी।

क्या मणिपुर हिंसा के पीछे विदेशी हाथ है?

मे. सरस चंद्र त्रिपाठी (रिटा.)

क्या मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है? अगर खुफिया एजेंसियों की मानें तो इसका जवाब हां है। सैन्य खुफिया सहित भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस कोण का मजबूत संबंध पाया है और पूर्वोत्तर में संकट को हवा देने में चीन की बढ़ती भूमिका से सावधान किया हैं। सूत्रों ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन सनराइज की सफलता के बाद चीन भारत-म्यांमार सहयोग को तोड़ने और क्षेत्र में विद्रोही नेटवर्क को पुनर्जीवित करने के लिए बेताब है। 2019 में भारत और म्यांमार की सेनाओं ने उत्तर पूर्व में सक्रिय विद्रोही समूहों के शिविरों को निशाना बनाकर म्यांमार सीमा पर संयुक्त अभियान के दो चरण शुरू किए थे। इस रणनीति का उद्देश्य उग्रवादी समूहों को नष्ट करना था जो भारत और म्यांमार दोनों को प्रभावित कर रहे हैं। चीनी रणनीति पूर्वोत्तर को अस्थिर करने की है ताकि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी चुनौती का सामना करने की बजाय भारतीय सेना वहीं बंधी रहे। चीन भारत को बाहर रखते हुए म्यांमार और बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक एक व्यापार मार्ग विकसित करने का भी इच्छुक है।

कुख्यात गोल्डन ट्राएंगल (वह क्षेत्र जहां थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाएं रुआक और मेकांग नदियों के संगम पर मिलती हैं) से पूर्वोत्तर में नशीले पदार्थ और अवैध शराब भेजने के पीछे चीन का हाथ बताया जाता है और वह म्यांमार की सेना को आपूर्ति करता रहा है। साथ ही पीडीएफ जैसे विद्रोही समूह भी इस क्षेत्र को अस्थिर रखने के लिए चीन के सहयोग से सक्रिय है। म्यांमार के काचिन राज्य में, जहां काचिन इंटीग्रेटेड फोर्स (केआईएफ) सेना से लड़ रही है, चीन दोनों का वित्तपोषण कर रहा है। चीन ने कथित तौर पर पूर्वोत्तर भारत में काचिन आदिवासियों की घुसपैठ में मदद की है। उनमें से ज्यादातर ड्रग्स और अन्य कंट्राबेंड लेकर भारत में दाखिल हुए हैं। भारतीय सेना के सूत्रों का कहना है कि दक्षिणी म्यांमार में, चीन भारत में गड़बड़ी पैदा करने के लिए पीडीएफ को

वित्तपोषित करता है। चुराचांदपुर में घटनास्थल से चीनी हथियार बरामद किए गए थे। एक प्रमुख अमेरिकी दैनिक की रिपोर्ट के अनुसार चीन म्यांमार को अस्थिर रखना चाहता है और इसे भारत विरोधी गतिविधि के केंद्र में बदलना चाहता है, जैसा कि उसने पाकिस्तान में किया था। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट में चीन का स्पष्ट हाथ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद चीन म्यामांर में जो कर रहा है, उसे देखने के बाद यह काफी संभव है।

पड़ोसी म्यांमार में 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद शरणार्थियों की आमद, विशेष रूप से सागैंग क्षेत्र से, जिनके कुकी लोगों के साथ मजबूत संबंध हैं; ने मैतेई स्वदेशी समुदाय के लिए असुरक्षा की भावना भी पैदा की है। हालांकि संघर्ष में वास्तविक निर्णय लेना उन लोगों के पास है जो बंदूक, ड्रग्स और राजनीति को नियंत्रित करते हैं, लेकिन दोनों समुदायों में सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं और बच्चे हैं। वर्तमान संघर्ष में कुछ लोगों के एजेंडे के अनुरूप विभिन्न जातीय समुदायों की पहचान को हथियार बनाया गया है। मणिपुर में 3 मई से मुख्य रूप से दो स्थानीय जातीय समुदायों, मैतेई और कुकी के बीच बार-बार अंतर-जातीय संघर्ष हुए हैं। राज्य में तीसरे प्रमुख समुदाय, नागा, इस बार तटस्थ रहे। हिंसा में 80 से अधिक मौतें हुई हैं और कम से कम 1,700 इमारतों (घरों और धार्मिक स्थलों) को जला दिया गया है। 35,000 से अधिक लोग वर्तमान में विस्थापित भी हैं, जिनमें से कई अब राज्य के 315 राहत शिविरों में से किसी एक में रह रहे हैं। जैसे-जैसे लड़ाई जारी है, ये संख्या बढ़ भी सकती हैं। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया काफी हद तक पारंपरिक रही है जैसे कर्फ्यू का आदेश देना, इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना और लगभग 17,000 सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को चरम मामलों के लिए शूट-ऐट-साइट आदेशों के साथ तैनात करना।

जैसा की ज्ञात है कि हिंसा हाई कोर्ट के फैसले के बाद भड़की थी जिसमें राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को एसटी के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया गया था। यह स्थिति मैतेई को अनुसूचित जनजाति (जो नागा और कुकी को पहले से ही प्राप्त कर रहे हैं) के लाभों को उन तक पहुंचने की अनुमति देगी। इसमें सरकार में आरक्षित सीटें और, सबसे महत्वपूर्ण, राज्य में कहीं भी जमीन खरीदना और वहां बसना शामिल है। अब तक राज्य की सबसे बड़ी आबादी वाले मैतेई आदिवासी क्षेत्रों में भूमि नहीं खरीद सकते हैं जो लगभग 90त्न भूमि क्षेत्र हैं। 3 मई को न्यायालय की घोषणा के तुरंत बाद हिंसा शुरू हो गई और कुकी ने सरकारी और मैतेई की निजी संपत्तियों को जलाना, दंगा करना और तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिया। सेना की एक आंतरिक रिपोर्ट से पता चला है कि 46 असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी (मूल रूप से भारतीय सेना की कुमाऊ रेजिमेंट से) की हत्या मिजोरम में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के उनके प्रयासों के कारण की गई थी, जब वह 2019-20 में मिजोरम में तैनात थे। आइजोल में उनकी बटालियन ने एक महीने में 80 करोड़ की चीनी ड्रग्स इंटरसेप्ट की थी। चुराचांदपुर में तैनात होने पर उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि वे नशे के धंधे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि रैकेट का हिस्सा रहे ग्रामीणों ने पीएलए पोषित स्लीपर सेल को घात लगाकर हमला करने और उनकी हत्या करने की हर आवश्यक सूचना दी।

म्यांमार में सत्ता परिवर्तन के बाद चीन के लिए यह बहुत आसान हो गया है कि वह भारत में हथियारों, गोला-बारूद और प्रशिक्षित विद्रोहियों को धकेल सके। मोरेह सीमा के पास रहने वाले भारतीय, चीनी सांठगांठ को समझने की अज्ञानता के कारण, अभी भी यह मानने से इनकार करते हैं कि चीन खतरा पैदा करता है। जबकि स्थानीय निवासियों के बेहिचक समर्थन ने म्यांमार के लोगों को मणिपुर/मिजोरम में आकर व्यापार करने के लिए उत्साहित किया है। म्यांमार की सेना से उत्पीड़न से आश्रय पाने के बहाने और भारत और म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजीम का लाभ उठाने के बहाने ड्रग पैडलर और चीन द्वारा प्रशिक्षित विद्रोही म्यांमार के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं। असल में भारत म्यामांर सीमा के पास रहने वाली जनजातियां स्वतंत्र रूप से सीमा पार कर सकती हैं और बिना वीजा के दोनों ओर 16 किमी की यात्रा कर सकती हैं। इसी कानूनी प्रावधान का लाभ घुसपैठिये उठा रहे हैं। मणिपुर में उत्पन्न हुई इस समस्या का समाधान कई मोर्चों पर कार्य करने से ही संभव होगा। बातचीत के माध्यम से मैतेई और कुकी दोनों की चिंताओं को दूर करना पहला कदम होगा। इसी के साथ चीन से कूटनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक रूप से निपटने की आवश्यकता है। मणिपुर में सत्ता परिवर्तन भी वर्तमान हिंसा को शांत कर सकता है, क्योंकि एन वीरेन सिंह को हाई हैंडेड व्यक्ति के रूप में माना जाता है। यहां तक कि अफ्सपा हटाने के बाद, राज्य सरकार सेना से जिस तरह व्यवहार करती रही है, उससे सेना भी एन बीरेन सिंह सरकार से खुश नहीं है।

कृपया इनसे सीखें

कुआँ खोदकर लोगों की प्यास बुझाना लक्ष्य

सीताराम लोधी

हमारे यहाँ सूखे के मौसम में पीने के पानी का कोई साधन नहीं हैं, खेती करने की बात तो छोड़ ही दीजिए और न ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि कुएँ या नल का इंतजाम कर सकें। मेरे गाँव के लोग गाँव में कुछ दूर जाकर एक जगह से पीने का पानी लाते थे। मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड इलाके में आने वाला यह जिला सूखा प्रभावित माना जाता है। मैंने गाँव के कई लोगों को पानी की कमी की वजह से पलायन करते देखा है। इसलिए जब मुझे इस समस्या का एहसास हुआ, तो मैंने अकेले ही कुआँ खोदने का फैसला किया। कुआँ खोदना कोई आसान काम नहीं है, इस बात को मैं और मेरे परिवार के लोग अच्छे से समझते थे। इसलिए जब मैंने अपना विचार उन्हें बताया तो परिवार वालों ने मुझे यह काम करने से मना भी किया। वे कुआँ खोदने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कुआँ खोदने पर पानी मिलेगा ही। लेकिन मैं कुआँ खोदने का निर्णय ले चुका था। गाँव से कुछ किलोमीटर की दूरी से लोगों को पानी ढोकर लाना कठिन नहीं लगाता था। ऐसे में मैंने अपनी मेहनत पर भरोसा किया और अपनी योजना पूरी करने के लिए निकल पड़ा। उसके बाद मैंने अकेले ही वर्ष 2015 में अपने खेत की जमीन पर कुआँ खोदने का काम शुरु कर दिया। यह सिलसिला करीब 18 महीनों तक नियमित तौर पर चलता रहा। फिर एक दिन मेरी मेहनत ने रंग दिखाया और तकरीबन 33 फीट की गहराई पर पानी मिल ही गया। मेरे साथ परिवार और गाँव से सभी लोग बहुत ही खुश थे।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

1988 नासा ने स्पेस व्हेकिल एस-213 लॉन्च किया।
1991 फिलीपींस में माउंट पिनातुबो के विस्फोट ने वायुमंडल में कणों की मात्रा को जमा किया, जो लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस (0.9 डिग्री फ़ारेनहाइट) द्वारा वैश्विक तापमान को कम करने के लिए पर्याप्त है।
1994 इजरायल और वेटिकन ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया।
1996 द ट्रबल - द प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने मैनचेस्टर, इंग्लैंड के वाणिज्यिक केंद्र में एक ट्रक बम विस्फोट किया, जिसमें 200 से अधिक लोग घायल हो गए और इमारतों को व्यापक नुकसान पहुंचा।
1997 8 मुस्लिम देशों द्वारा इस्तांबुल में डी-8 नामक संगठन का गठन।
2005 जमैका के आसफा पावेल का एथेंस में 8.77 सेकेण्ड का समय लेकर 100 मीटर फर्राटा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

गायत्रीरहस्योपनिषद् (भाग-2)

गतांक से आगे...

उत्तर-भू: यह भूलोक का वाचक है, भुव: अन्तरिक्ष वाची है, स्व: स्वर्ग लोक का वाची है, मह: महर्लोक का वाचक है, जन: जनोलोक का, तप:- तपोलोक का, सत्यम् -सत्यलोक का, तत- तेजसूरूप अग्निदेव का, सवितु: यह सूर्य का वाचक है, वरेण्यं यह प्रजापति (ब्रह्मा) का, भर्ग- आप (जल) का, देवस्य यह तेजस्वी इन्द्र का, जो परम ऐश्वर्य का द्योतक सर्वपुरुष नामक रुद्र द्वारा प्रख्यात है। धीमहि यह अन्तरात्मा का, धिय: यह दूसरी अन्तरात्मा का ब्रह्म का य- यह उस भगवान् सदाशिव पुरुष का, न: यह अपने स्वरूप का (अर्थात् हमारे इस अर्थ का वाचक है), इस तरह से सभी यथोक्त क्रम से सतत स्वरूप का बोध (साक्षात्कार) कराने वाले हैं। प्रचोदयात् यह प्रेरणा की इच्छा का द्योतक है जो धर्म इन सभी लोकों का आश्रय करा दे, वही गायत्री है।

प्रश्न- वह गायत्री किस गोत्र वाली है, कितने अक्षर वाली है, कितने पाद वाली, कितनी कुक्षि वाली हैं और उसके शीर्ष मूर्धादि स्थल क्या हैं? उत्तर- वह सांख्यायन गोत्र वाली, चौवीस अक्षर वाली, गायत्री तीन एवं चार पाद वाली है। तदनन्तर उसके चार पाद, छ: कुक्षियाँ एवं पाँच शिर हैं। प्रश्न- इसके पाद कौन हैं ? कुक्षियाँ कौन हैं? तथा शिर कौन हैं? उत्तर- ऋग्वेद इसका प्रथम पाद है, यजुर्वेद द्वितीय पाद है, सामवेद तृतीय पाद है और चतुर्थ पाद अथर्ववेद है। इसकी पूर्व दिशा प्रथम कुक्षि है, दक्षिण दिशा द्वितीय कुक्षि है, पश्चिम दिशा तृतीय कुक्षि है, उत्तर दिशा चौथी कुक्षि है। ऊर्ध्वभाग पाँचवीं कुक्षि है एवं अध: भाग छठी कुक्षि है। व्याकरण इसका प्रथम शिर, शिक्षा द्वितीय शिर, कल्प तृतीय शिर, निरुक्त चतुर्थ एवं ज्योतिष पञ्चम शिर है। प्रश्न-कौन सी दिशा में किस रंग की अधिष्ठात्री देवियाँ प्रतिष्ठित हैं? उनका विस्तार क्या है? स्वर-लक्षण क्या हैं? किन अक्षरों को वह अधिष्ठात्री देवियाँ हैं? उनके ऋषि कौन हैं ? छन्द कौन हैं? शक्तियाँ कौन हैं? तत्त्व कौन हैं एवं उनके अवयव कौन हैं? उत्तर-पूर्व दिशा में गायत्री स्थित हैं (इनका वर्ण लाल है)। मध्यमा अर्थात् दक्षिण दिशा में (श्वेत वर्ण वाली) सावित्री स्थित हैं। पश्चिम दिशा में (कृष्ण वर्ण युक्त) सरस्वती विद्यमान हैं, यही ध्यान करना उचित है। पृथिवी, आकाश तथा स्वर्ग इन (त्रिशक्तियों) के विस्तार स्थल एवं निवास स्थान हैं।

क्रमश:...

वैश्विक पवन दिवस

हर साल 15 जून को वैश्विक पवन दिवस (ग्लोबल विंड डे) , पवन ऊर्जा (विंड एनर्जी) प्रदान करने वाली शक्ति और संभावनाओं के रूप में जश्न मनाया जाता है। यह लोगों के लिए हवा और इससे पैदा होने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा के बारे में अधिक जानने का भी दिन है। क्या आपने कभी हवा के बारे में शिकायत की है? कभी-कभी हवा पूरी तरह से एक खूबसूरत दिन को बर्बाद कर देती है। हवा भी धूल और मलबे को चारों ओर उड़ा देती है।

हवा की एक और शिकायत यह है कि इससे मिट्टी का क्षरण होता है। यदि यह बहुत तेज है, तो हवा पेड़ों को गिरा देती है और अन्य प्रकार का नुकसान का कारण बनती है। लेकिन हवा के अच्छे काम भी हो सकते हैं। कई कंपनियां एक किफायती प्रकार की ऊर्जा के रूप में हवा को अपना रही हैं। ये कंपनियां पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन टरबाइन का उपयोग करती हैं। ऊर्जा विभाग के मुताबिक पवन ऊर्जा निम्नलिखित फायदे प्रदान करती है- यह ऊर्जा के सबसे किफायती स्रोतों में से एक है। पवन ऊर्जा जीवाश्म

ईंधन या कोयले पर निर्भर नहीं है, जो इसे एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत बनाती है। यह ऊर्जा का एक स्थायी स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होगा। पवन ऊर्जा भी रोजगार पैदा करती है। कई देश पवन ऊर्जा लाभ उठा रहे हैं। दुनिया भर में पवन ऊर्जा के कुछ शीर्ष उत्पादकों में चीन, जर्मनी, भारत, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील शामिल हैं।

यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन (ईडब्ल्यूईए) ने 2007 में पहला विंड डे आयोजित किया। 2009 में ईडब्ल्यूईए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (जीडब्ल्यूईसी) के साथ जुड़ गया और इसे एक विश्वव्यापी कार्यक्रम बना दिया। हाल के वर्षों में, विंडयूरोप और जीडब्ल्यूईसी ने एक साथ इस दिन का आयोजन किया है। 2012 में संगठनों ने एक फोटो प्रतियोगिता प्रायोजित की। दुनिया भर के लोगों को उन तस्वीरों को दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जो वर्ष के लिए थीम को सर्वश्रेष्ठ रूप से कैप्चर करती हैं। हाल के विषयों में दि विंड इन माइंड और फ्यूचर विंड शामिल हैं। वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दुनिया भर में हर साल पवन ऊर्जा प्रतिष्ठानों को इस दशक के भीतर, 2021 में स्थापित 94 गीगावाट से चौगुना होना चाहिए। आवश्यक प्रवर्धन के बिना, पूर्व-औद्योगिक स्तरों पर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना जो कि पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित लक्ष्य है और 2050 तक कुल शून्य उत्सर्जन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। 2022 में नए ऑफशोर या अपतटीय प्रतिष्ठानों के 2019-2020 के स्तर तक घटने की संभावना है, मुख्य रूप से चीन में प्रतिष्ठानों की कमी के कारण। बाजार की वृद्धि 2023 से फिर से गति प्राप्त करने की उम्मीद है, अंतत: 2026 में 30 गीगावाट को पार कर जाएगी। ऑफशोर या अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पादन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ निवेश पर लाभ को बढ़ाता है। 2021 में 1.4 गीगावाट से अधिक पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी, जो पिछले वर्ष के 1.1 गीगावाट अधिक था।

अपना कुनबा क्यों बढ़ाना चाहती है भाजपा

उमेश चतुर्वेदी

राजनीति में सिद्धांत और विचारधारा की खूब दुहाई दी जाती है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए पार्टियां सिद्धांतों और विचारों को किनारे रखकर नए कदम उठा लेती हैं। फिर नए कदमों के बचाव में सिद्धांतों और विचारों की बुनियाद पर वे नए तर्क गढ़ती हैं। अगर जनता ने इसे मान लिया तो बल्ले-बल्ले, नहीं तो पार्टियां नए रास्ते पकड़ लेती हैं। तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) का बीजेपी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना राजनीति की इसी रवायत का उदाहरण है। महज पांच साल पहले टीडीपी के बॉस एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग पर एनडीए से अपनी राह अलग कर ली थी। लेकिन पांच साल तक सत्ता से दूर रहने के बाद नायडू अपनी आइडियॉलजी बदलने के लिए मजबूर होते दिख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से नायडू की मुलाकात के बाद अब तय माना जा रहा है कि टीडीपी एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनेगी।

कुछ ऐसी ही बात बीजेपी के साथ भी है। पहले हिमाचल और फिर कर्नाटक की हार ने बीजेपी के आत्मविश्वास को हिला दिया है। अगले कुछ महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी उसकी चुनावी परीक्षा होनी है। ऐसे में वह अपनी रणनीति पर दोबारा गौर करने को मजबूर हो गई है। शायद यही वजह है कि वह अपने पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल और टीडीपी के साथ अलायंस की संभावनाएं तलाश रही है।

अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में टीडीपी,

एनडीए सरकार में भले ही शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वह बाहर से मजबूत सहयोगी थी। इसका फायदा भी उसने खूब उठाया। चंद्रबाबू नायडू तब अपने राज्य के लिए तमाम तरह की योजनाएं और अनाज का विशेष और बड़ा कोटा उठा लेते थे। राम मंदिर और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के रुख पर सवाल भी उठाते रहते थे। तब की राजनीति में टीडीपी की स्थिति चित्त भी मेरी और पट भी मेरी वाली थी। तब नायडू बीजेपी को राज्य की राजनीति में दबाकर भी रखते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बीजेपी का वोट बैंक उनका सहारा बनेगा, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में बीजेपी, टीडीपी के वोट बैंक को ऐसा सहारा दे सकती है, जिससे चुनावी इतिहास बदल सके। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना में बीजेपी ने तेजी से पांव पसारे हैं। उसे राज्य में सत्ता के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी का संकट यह है कि उसके पास 119 सीटों के लिए उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में अगर टीडीपी से उसका समझौता होता है तो उसकी चुनौती कम होगी। दोनों दल मिलकर लड़ें तो के चंद्रशेखर राव की सत्ता उखड़ सकती है।

बीजेपी सहयोगियों की तलाश में जिस तरह जुटी हुई है, उससे साफ है कि वह अपने राजनीतिक किले को मजबूत करने में कोई कसर बाकी रखना नहीं चाहती। उसकी रणनीति को समझने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले मन की बात कार्यक्रम पर ध्यान देना होगा। उसमें प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आंध्र प्रदेश से उखाड़ फेंकने वाले तेलुगू बिड्डा नंदमुरि तारक रामाराव को याद किया। एनटीआर के रूप में मशहूर रामाराव सात साल तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं रामाराव के दामाद और उत्तराधिकारी हैं नारा चंद्रबाबू नायडू। प्रधानमंत्री का मन की बात में एनटीआर को याद करना चंद्रबाबू के लिए कदम बढ़ाने का बहाना बन गया।

शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी के रिश्तों की बर्फ तब पिघली, जब प्रधानमंत्री अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद शोकसभा में शामिल होने पहुंचे। किसान आंदोलन के समर्थन में अकाली दल ने एनडीए से अलग राह चुन ली थी। लेकिन पंजाब विधानसभा चुनावों में उसे खास फायदा नहीं मिला तो उसे भी अपनी रणनीति को लेकर सोचना पड़ा। अब उसका भी रुख बदला नजर आ रहा है। बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। उसमें जम्मू-कश्मीर की प्रमुख पार्टी नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शामिल होने से मना कर दिया है। उन्होंने तर्क दिया है कि जब 370 हटाया जा रहा था, तो ये दल चुप थे। उमर ने पटना बैठक से दूरी रखने का ऐलान करके बीजेपी को ही संकेत दिया है। चुनावी गठबंधन में वह भी बीजेपी के साथ हो सकते हैं। बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश के ओमप्रकाश राजभर के भी जाने की चर्चा है। ऐसी चर्चाएं हर राज्य के उन छोटे दलों को लेकर है, जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं। कर्नाटक में मौजूदा कांग्रेस सरकार की पांच गारंटी को लेकर जनता दल एस जिस तरह का बयान दे रहा है और जिस तरह नई संसद के उद्घाटन में एचडी देवेगौड़ा शामिल हुए, उससे साफ है कि बीजेपी और जनता दल एस के बीच सहयोग के लिए समझ बन रही है। इन संकेतों से लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का कुनबा बढ़ेगा। विपक्षी जुटान के खिलाफ मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए भी कुनबा विस्तार जरूरी है। जब ऐसा हो जाएगा तो तय मानिए कि विचार और सिद्धांत की बुनियाद में ऐसे तर्क गढ़ लिए जाएंगे, जो गठबंधन की जरूरत की कारगर व्याख्या होंगे।

बापू की दिनचर्या

दिन का भोजन (भाग-4)

गतांक से आगे...

आश्रम में नए लोगों को आरंभ में यह सब विचित्र-सा लगना स्वाभाविक था। काशिनाथजी त्रिवेदी के शब्दों में धीरे-धीरे नित्य के अभ्यास से जीभ का मूल स्वाद लौट आता मिर्च मसाले की चाट से विकृत बनी जीभ क्रमश- अपना प्रकृत स्वास्थ्य प्राप्त कर लेती और फिर तो आरंभ में बेस्वाद लगनेवाली उबली साग-सब्जी भी लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगती। इससे आहार में सहज ही संयम सधता, स्वाद के वश होकर आवश्यकता से अधिक खाने की आदत छूटती, शरीर में आलस्य का संचार कम होता और भोजन के बाद स्फूर्ति के साथ काम में लगे रहने की आदत बनती। स्वास्थ्य सुधरता हो, शरीर सशक्त भी बनता अति आहार से उत्पन्न होनेवाले रोगों 1 से अनायास रक्षा होती और अन्न को ब्रह्म समझने तथा जीने के लिए खाने की स्वस्थ वृत्ति का जीवन में उदय होता। इस तरह अपने अस्वादव्रत के निमित्त से बापू मनुष्य के और समाज के जीवन में आत्मसंयम और आत्मानुशासन को सुदृढ करते। व्रत के विषय में बापू के विचार बहुत स्पष्ट और दृढ़ थे। व्रत अनादर अथवा भंग उनसे सहन नहीं होता। आश्रम के बच्चों अथवा बड़ों में कोई भी जब किसी व्रत का जाने-अनजाने भंग करता तो वे तुरंत प्रेम-भाव से या तो उसका प्रायश्चित्त कराते या व्रत भंग करनेवाले साथी की आत्मा को जगाने के लिए स्वयं प्रायश्चित्त करते। इस प्रकार वे सारे वातावरण को शुद्ध-बुद्ध बनाए रखते। खुराक से प्राप्त होनेवाले वनस्पतिजन्य नमक को बापू पर्याप्त बताते। समुद्री या खान के नमक के संबंध में उनका कहना था कि वह उसी रूप में पसीने या दूसरे रास्ते से शरीर से निकल जाता है। उसका कोई विशेष उपयोग शरीर में नहीं होता। वे खाँसी, दमा, बवासीर और रक्त प्रवाह जैसे रोगों में नमक के त्याग से उन पर नियंत्रण करना आसान बताते। नमक त्यागने से जल कम पीने तथा आलस्य में कमी होने की बात भी कहते।

क्रमश: ...

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ में 26 जून तक स्कूल बंद गर्मी के चलते सीएम ने जारी किए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 26 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बढ़ती तेज गर्मी और लू के चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश जारी किए हैं। पहले स्कूल 15 जून तक के लिए स्कूलों में छुट्टियां की गई थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में बढ़ती गर्मी और लू से बच्चों की सुरक्षा जरूरी है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद प्रदेश में 16 जून से फिर स्कूलों को खुलना था। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों के हित में स्कूल खुलने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। इस वक्त राज्य के कई जिलों में गर्म हवाएं चल रही हैं। कई जगहों पर लू के हालात हैं। इसे देखते हुए राज्य शासन ने आंशिक संशोधन करते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाया है।

आबकारी मंत्री ने ओरछा के विद्यार्थियों को किया जाति प्रमाण पत्र वितरित

नारायणपुर। अबूझमाड़ में स्कूली छात्र-

छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र मिलना शुरू हो गया है। नारायणपुर जिले के सुदूर ओरछा विकासखण्ड के अबूझमाड़ के पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को आबकारी मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और विधायक चंदन कश्यप ने स्कूली बच्चों को बुधवार को जाति प्रमाण पत्र का वितरण किया। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश पर शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही जिला प्रशासन ने जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया है।

शा. उचित मूल्य की 10 दुकानों पर ताला, प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निलंबित

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य की 10 राशन दुकानों पर ताला जड़ दिया है। भाटापारा एसडीएम नरेंद्र बंजारा ने यह कार्रवाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन मिलने पर की है। आदेश में कहा गया है कि सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक और विक्रेताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के कारण समितियों की ओर से संचालित दुकानों से लोगों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके चलते इन दुकानों को निलंबित किया जाता है।

बस्तर संभाग में 9 उपपुलिस अधीक्षकों की नई पदस्थापना की गई

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह (पुलिस) मंत्रालय की ओर से परिवीक्षा अवधि पूरी कर चुके 09 उपपुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारियों को नई पदस्थापना बस्तर संभाग में करने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहकर प्रशिक्षण ले रहे उपपुलिस अधीक्षकों सौरभ उईके, राहुल शर्मा, सुश्री नुपुर उपाध्याय, सुश्री गरिमा दादर, प्रशांत देवांगन, मनीष रात्रे, सुश्री दीपमाला कुर्रे, आशीष नेताम एवं मनोज कुमार मंड़ावी की नई पदस्थापना बस्तर संभाग के कांकेर, सुकमा नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिलों में अस्थाई रूप में आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया है, जहां वे अपनी सेवाएं देगे।

नीट में सारांश पटेल बने छत्तीसगढ़ टॉपर बताए सफलता के तीन मंत्र

रायपुर। नीट के परीक्षा परिणाम मंगलवार देर शाम जारी कर दिए गए। छत्तीसगढ़ में इस साल से 42130 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे। इनमें से 41196 ने परीक्षा दी थी और 17610 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनमें रायपुर के सारांश पटेल ने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। सारांश को 690 अंक मिले हैं और ऑल इंडिया रैंकिंग 824 है। पहले ही प्रयास में सफलता हासिल करने वाले सारांश ने नए परीक्षार्थियों के लिए तीन मंत्र भी बताए हैं। सारांश पटेल ने बताया कि कोचिंग के साथ-साथ उनके पिता और बड़े भाई उनकी पढ़ाई में मदद करते थे। उनके पिता रेलवे में इंजीनियर हैं। बड़े भाई सानिध्य एनआईटी के आईटी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहा है। उनका भाई फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे विषयों में सहायता करते थे। सारांश रोजाना आठ से 10 घंटे की पढ़ाई का टारगेट लेकर चलते थे। इस बीच उनकी मां उन्हें पढ़ाई के लिए मोटिवेट करती थी।

उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

धमतरी। जिले के उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ों को काटकर अतिक्रमण करने वाले 50 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है।

इस कार्रवाई से अतिक्रमण कारियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सीतानदी उदंती अभ्यारण के कक्ष क्रमांक 322, 353 नागबेल बीट के घोटबेड़ा घुरावड़ के जंगल में 468 पेड़ों को काटा गया है। जिसके बाद करीब 100 एकड़ वन भूमि में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। वहीं कुछ दिनों पहले वन विभाग ने अवैध कब्जा पर बुलडोजर चलाया। जिसके बाद धमतरी वन विभाग की टीम ने अतिक्रमणकारी 36 पुरुष और 14 महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया जा रहा: मरकाम

ट्विटर के पूर्व सीईओ के खुलासों पर बोले - जनता की आवाज मोदी सरकार दमन कर रही

रायपुर। कांग्रेस ने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के खुलासों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ट्विटर के पूर्व सीईओ ने जो खुलासे किए हैं, वह अत्यंत गंभीर हैं। आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया जा रहा है। डोर्सी के खुलासों से यह एक बार फिर साबित हो गया है कि मौजूदा भाजपा सरकार साजिश रचकर देश में लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने केविन एप से देशवासियों के डाटा लीक होने को लेकर भी सरकार से कई सवाल किए हैं।

मरकाम ने कहा कि ट्विटर के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जैक डोर्सी ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि ट्विटर को देश में किसानों के प्रदर्शन के दौरान सरकारी दबाव और बंद किये जाने की धमकियों का सामना करना पड़ा था। इससे एक बार फिर

साबित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं और वह तानाशाह होने के साथ कायर भी हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। राहुल गांधी जी की इस बात पर आज एक बार फिर से मुहर लग गई है।

उन्होंने कहा कि काले कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने एक साल से भी अधिक समय तक आंदोलन किया। भीषण गर्मी, बारिश, ठंड,की परवाह किए बगैर किसान अपने अधिकार के लिए डटे रहे। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी कहा गया था। मगर तानाशाह किसी की सुनने को तैयार नहीं था। अपने घमंड और अहंकार में चूर देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा, जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को बोला गया था कि अगर किसानों को दिखाया तो उनके दफ्तरों पर, उनके कर्मचारियों के घर पर छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद चुनावी नफा-नुकसान देखते हुए तीन काले कृषि कानून वापस लिए, लेकिन ये सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनपर दमनपूर्वक कार्रवाई कर उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे थे।

मरकाम ने कहा कि भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री आईटी सेल और भाजपा नेताओं ने टूलकिट का मुद्दा उठाया था और कहा था कि कांग्रेस टूलकिट का इस्तेमाल कर रही है। उस टूलकिट को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया कहा था। इसके बाद 24 मई, 2021 को ट्विटर के कार्यालयों पर छापा पड़ा, ट्विटर के कर्मचारियों के घर पर छापा पड़ा। यह सब किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। ट्विटर ही नहीं भाजपा सरकार के काले कारनामों को उजागर करने वाले दैनिक भास्कर, न्यूज क्लिक, द वायर, एनडीटीवी पर भी छापेमारी की गई। सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई, उसे दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को सरकार के इशारे पर ब्लॉक किया गया था। इससे भी सरकार का मन नहीं भरा तो छह महीने तक के लिए उनके अकाउंट की फॉलोवर ग्रोथ भी धीमी कर दी गई। ट्विटर जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर भी सरकार सच को दबाने का काम कर रही है। फेसबुक, यूट्यूब पर भी यही हो रहा है।

रक्तदान से जरूरतमंदों की होती है प्राणों की रक्षा : मंत्री लखमा

रायपुर। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बस्तर (जगदलपुर) जिला रेडक्रॉस सोसायटी के तत्वाधान में महारानी अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री एवं बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने कहा कि रक्तदान पुण्य का कार्य है। रक्तदान से जरूरतमंदो की प्राणों की रक्षा होती है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अक्सर रक्त की आवश्यकता होती है। कई बार समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने पर व्यक्ति की जान संकट में आ जाती है। किसी व्यक्ति का जीवन रक्त के अभाव में संकट में न पड़े, इसके लिए रक्तदान मानवता के लिए जरूरी है। मंत्री श्री लखमा ने रक्तदान के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर खुशी जताते हुए कहा कि लोगों के जीवन को बचाने की यह ललक प्रेरणादायी है। मंत्री श्री लखमा ने कहा कि रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा निरंतर रचनात्मक कार्य किया जा रहा है। उन्होंने रक्तदाताओं को बधाई देते हुए कहा कि रक्तदाताओं के इस पुनित कार्य से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो पाएगी। ऐसा पुनित कार्य दूसरों के जीवन के प्रति संवेदनशील रखने वाले व्यक्ति ही सहजता के साथ रक्तदान कर सकता है। रक्तदान से मन को सुकून मिलता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में युवोदय के स्वयंसेवक तथा एनसीसी कैडेट्स ने रक्तदान किया।

बुधवारी बाजार के सब्जी मार्केट की 15 दुकानें जलकर हुई राख

बिलासपुर। रेलवे क्षेत्र के बुधवारी बाजार में स्थित सब्जी मार्केट में बुधवार की अलसुबह बिजली कनेक्शन में स्पार्क होने के कारण 15 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है वहीं लोगों का कहना है कि करीब 25 गुमटियां आग की चपेट में आई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे क्षेत्र के बुधवारी बाजार में कपड़े और अन्य जरूरी सामान के अलावा सब्जी मार्केट भी है। यहां पर व्यापारी दिनभर व्यवसाय के बाद अपने सामान दूसरी जगह पर रखते हैं। व्यापार के लिए बांस और तिरपाल के सहारे गुमटियां बनाई गई है। मंगलवार को व्यवसाय के बाद व्यापारी अपने सामान लेकर घर चले गए थे। बुधवार की सुबह किसी ने धुंआ निकलते देख आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। तब तक आग की चपेट में कई दुकाने आ गई थी। आगजनी की जानकारी लगते ही तोरवा पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाने कोशिश की गई। कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। तोरवा थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने बताया कि आग से करीब 15 गुमटियां जलकर राख हो गई है। वहीं, व्यापारियों का कहना है कि आग से 25 व्यापारियों को नुकसान हुआ है। आगजनी की किसी ने शिकायत नहीं की है। पुलिस का मानना है कि दुकान के लिए लगाए बिजली कनेक्शन में स्पार्क के कारण आग लगी होगी। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी ली जा रही है।

सिंहदेव को पता है अगली बार कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी: बृजमोहन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि, टीएस सिंहदेव को पता है कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने सरकार बनने की बात पर संदेह जताया। यह उनके दिल की बात थी, जो जुबाान तक आ गई। ऐसा एक बार नही पच्चीसों बार आई है। बाद में जब उनकी पार्टी का दबाव पड़ता है तो कह देते हैं मैं कांग्रेसी हूं, मैं तो चाहूंगा कांग्रेस की सरकार बने। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बयान पर विधायक बृजमोहन प्रतिक्रिया दे रहे थे।

असली राजा अपमान बर्दाश्त नहीं करता

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि, असली राजा अपमान बर्दाश्त नहीं करता है। आज टीएस सिंहदेव के साथ जो कुछ भी हो रहा है, सब देख रहे हैं। कहा कि यह समझ से परे है कि वो अपमान बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? आखिर मजबूरी क्या है? टीएस सिंहदेव कांग्रेस के जनघोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे हैं। अग्रवाल ने कहा कि लोग जब उनसे मिलने जाते है और वादों पर सवाल करते है, तो सिंहदेव का जवाब होता है कि मेरे हाथों में मांगों को पूरा करना नहीं है।

साबित हो गया, जुबान के पक्के राजा नहीं हैं

बृजमोहन ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वादाखिलाफी की है। शराबबंदी का वादा, सभी बोराजगारों को भत्ता देने जैसे कई वादे जन घोषणा पत्र में किए गए थे। सिंहदेव राज परिवार की प्रतिष्ठा प्रदेश में रही है। इसलिए जनता ने उनके बनाए जन घोषणापत्र पर भरोसा जताया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की आज भरोसा पूरी तरह से टूट गया और यह साबित हो गया है कि वो जुबान के पक्के राजा नहीं हैं।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी रीना लारिया की सेवा समाप्त

कांकेर। कलेक्टर डॉ प्रियंका शुक्ला द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी (संविदा) श्रीमती रीना लारिया की सेवा समाप्त कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रतिज्ञा विकास संस्थान दुर्ग द्वारा जिला मुख्यालय कांकेर में संचालित विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था के विरुद्ध बच्चों के साथ यातना एवं दुर्व्यवहार की शिकायत पाये जाने पर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 04 जून 2023 को दत्तक ग्रहण अभिकरण का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में संस्था के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की पुष्टि हुई है। घटना के संबंध में जांच दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में श्रीमती रीना लारिया के कथन अनुसार विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण संस्था में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी होने की स्वीकारोक्ति है। उसके बावजूद भी कार्रवाई हेतु वरिष्ठतम अधिकारियों को सूचित नहीं करना उसके पदीय दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। घटना के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्रीमती रीना लारिया द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया एवं उनके द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई। जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्रीमती रीना लारिया (संविदा) के विरुद्ध 30 मई 2023 को भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में 05 जून 2023 को कार्यालय मुख्यमंत्री निवास, छत्तीसगढ़ शासन से भी जांच हेतु पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें वर्णित शिकायत अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के पूर्व कर्मचारी (संविदा) द्वारा तत्कालीन पद से त्याग पत्र देने के बाद भी वर्ष 2022-23 का कार्यालयीन रोकड़-बही का संधारण किया गया है। शिकायत के सन्दर्भ में कलेक्टर कार्यालय द्वारा जांच समिति बनाई गई थी। समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में श्रीमती रीना लारिया एवं पूर्व कर्मचारी (संविदा) द्वारा दिये गये कथनों से शिकायत की पुष्टि होती है। उपरोक्त कारणों से श्रीमती रीना लारिया, जिला बाल संरक्षण अधिकारी (संविदा) की सेवा कलेक्टर द्वारा समाप्त कर दी गई है।

रविंद्र चौबे से अचानक मिलने पहुंचे सीएम भूपेश

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को अचानक कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। मंत्री रविन्द्र चौबे के बंगले जाने का मुख्यमंत्री का यह प्रोग्राम अचानक तैयार किया गया। इसके पहले कोई सूचना जारी नहीं की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम के साथ मंत्री रविन्द्र चौबे का स्वास्थ्य जानने के लिए उनके बंगले पहुंचे हैं। जहां उन्होने मंत्री रविन्द्र चौबे से मिलकर उनका हालचाल जाना है। बताया जा रहा है कि रविन्द्र चौबे का स्वास्थ पिछले कुछ दिनों से खराब चल रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित दोनों नेता चौबे के बंगले पहुंचे और उनसे मुलाकात की। खबर है कि रवींद्र चौबे के बंगले पर ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा ने एक बैठक कर आगामी दिनों के चुनाव की रणनीति तैयार की है।

अचानक मुलाकात से सियासी गलियारों में हलचल तेज

बहरहाल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की रविन्द्र चौबे से क्या बातचीत हुई। इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन यह जरूर है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का मंत्रियों के बंगले जाना चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। लिहाजा सियासी गलियारों में अचानक इस मुलाकात को लेकर भी हलचल तेज हो गई।

छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कद्दावर कांग्रेस नेता हैं। रविंद्र चौबे 1977-80 तक भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन दुर्ग के जिलाध्यक्ष रहे। 1980-90 तक दुर्ग युवक कांग्रेस के महामंत्री/अध्यक्ष रहे हैं। 1985 में पहली बार चुनाव जीता और मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य बने। रविंद्र चौबे ने 1990, 1993, 1998, 2003, 2008 में भी चुनाव जीता। साल 2018 में उन्होंने सातवीं बार चुनाव जीता। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ के संसदीय कार्य मंत्री भी हैं।

पटवारी हड़ताल के एक महीने पूरे, अब एस्मा के बाद सरकार को पटवारियों ने दी धमकी

धमतरी। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल को एक महीने पूरे हो गए हैं। इस दौरान अब राजस्व निरीक्षकों ने भी पटवारियों के हड़ताल को समर्थन दिया है।इस दौरान पटवारियों को हड़ताल से वापस लौटने के लिए सरकार ने कहा।लेकिन नहीं मानने पर सरकार ने एस्मा लगा दिया। बावजूद इसके पटवारी आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं हैं।

धमतरी के गांधी मैदान में 8 सूत्रीय मांगों कों लेकर पटवारी पेड़ के नीचे लगातार धरना दे रहे हैं। इस हड़ताल के कारण राजस्व का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। वैसे चुनावी साल में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल और आंदोलन ज्यादा देखने को मिलते हैं। चुनावी साल में अपनी मांगें मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना आसान होता है। धमतरी में पटवारियों ने साफ कहा कि %%उनकी मांग ढाई साल पुरानी है। अब भी अगर सरकार नहीं मानती है तो आगामी चुनावों में इसका नुकसान सत्ताधारी दल को होगा।

छत्तीसगढ़ पटवारी संघ 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटवारियों की मांगें हैं कि, वेतन विसंगति को दूर कर

वेतन में बढ़ोत्तरी की जाए, वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन दिए जाएं। राजस्व निरीक्षक के कुल पदों मे 50 प्रतिशत पर पटवारियों के वरिष्ठता के आधार पर और 50 प्रतिशत पदों पर विभागीय परीक्षा के आधार पर प्रमोशन दिया जाए। 5 साल पूरा कर चुके पटवारियों को राजस्व निरीक्षक की ट्रेनिंग दी जाए।

इसके साथ ही पटवारियों ने संसाधन और भत्ते, स्टेशनरी भत्ता और अतिरिक्त प्रभार के हल्के का भत्ता दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हड़ताल और धरना प्रदर्शन के कारण सरकार को परेशानी हो सकती है।

क्या कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार थे टीएस सिंहदेव, बघेल के सामने किया खुलासा

सरगुजा। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन में प्रदेश के सबसे अहम सवाल से पर्दा लगभग उठ गया है। सरकार और कांग्रेस से लगातार नाराज नजर आने वाले मंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं के सामने बंद कमरे में कई भ्रम तोड़े। ये बात प्रदेश की सियासत के लिए सबसे अहम इसलिए है क्योंकि बार बार यह बात उठती है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के संकट मोचन रहे टीएस सिंहदेव क्या 2023 में भी कांग्रेस का साथ देंगे। विपक्ष भी इसी आस में थी कि सिंहदेव की नाराजगी का फायदा उनको मिलेगा। लेकिन आज कार्यकर्ताओ के सामने सिंहदेव ने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं।

दिल्ली के होटल में भाजपा नेताओं से मिलने गए थे टीएस सिंहदेव

कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहा कि दिल्ली के होटल अशोका में मैं भाजपा के बड़े नेताओं से मिलने भी गया था। शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जहां से ऑफर ना आया हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। कांग्रेस पार्टी के सिपाही के रूप में काम करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं, राजेश तिवारी और भूपेश बघेल की बहुत अच्छी दोस्ती है। हम तीनों ने साथ मिलकर काम किया।

टीएस सिंहदेव ने कहा भूपेश भाई के व्यवहार में कभी कोई कमी नहीं देखी मैंने, चाहे वो सार्वजनिक मंच हो या और कोई जगह। कुछ लोग हैं जो आपस में दरार पैदा कराकर खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए कई तरह की बातें होती हैं।

भूपेश बघेल और राजेश तिवारी के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि 14 में 14 सीट जीतना कठिन काम था। सबने मिलकर मेहनत की इसलिए ऐसे परिणाम आए। कांग्रेस में एक बात बुरी है जो मैं कहना चाहूंगा कोई रिकार्डिंग कर रहे हों प्लीज मत करिएगा, वो है गुटबाजी। उस समय हम लोगों में कोई गुटबाजी नहीं थी। एक साथ मिलकर काम किया और आगे भी एक साथ काम करने की जरूरत है।

सम्मेलन से बाहर आने के बाद सिंहदेव ने इस विषय पर मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। कहा वो भी आफ द रिकॉर्ड ही है। राजेश तिवारी जी ने कुछ बातों को उठाया। पुराने साथी रहे हैं, आज भी पारिवारिक मधुर संबंध है। उन्होंने बात को उठाया तो मुझे लगा की अगर बात उठ गई है तो खुलकर साथियों के बीच में चर्चा हो जाए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। साथ ही बीजेपी के कमजोर होने की भी बात कही है। लंबे समय से सस्पेंस और भूपेश बघेल से मतभेद की अफवाहों पर टीएस सिंहदेव ने अब लगभग पूर्ण विराम लगा दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले सिंहदेव को अपने खेमे में करने की ताक में बैठी बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है।

दिग्विजय का मुख्यमंत्री को लिखा पत्र सामयिक एवं मानवीय : रिजवी

रायपुर। मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह द्वारा शिक्षाकर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति के मसले को सामयिक एवं मानवीय निरूपित करते हुए शिक्षा कर्मियों की मांग का समर्थन किया है तथा शिक्षाकर्मियों की मांग को जायज बताया है तथा कहा है कि शिक्षाकर्मी की मृत्योपरांत परिवार को उजड़ने से बचाने के लिए उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाना वक्त का तकाजा है। रिजवी ने श्री दिग्विजय सिंह की सोच की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा है कि इस दिशा में उन्हें जल्द निर्णय लेकर मृत शिक्षाकर्मियों के आश्रितों की मांग पर अमल करने का निवेदन किया है।

कांग्रेस संगठन में चल रही आपसी कलहः साव

भ्रष्टाचार और घोटालों ने उन्हें अब अपने 'खानदानी आकाओं' से दूर कर दिया

रायपुर। प्रदेश भाजपा प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नबीन, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के चुनावी तैयारी की समीक्षा की। इस बैठक में संगठन के निर्देश पर मण्डल प्रवास पर गये पदाधिकारियों ने सभी 90 विधानसभा क्षेत्र की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक में मंडल प्रवास पर गए नेताओं ने अपनी रिपोर्ट में बताया की उन्होंने हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से बातचीत एवं उनके कार्यों की समीक्षा की ताकि आने वाले समय में पूरी आक्रामकता और सक्रियता के साथ आने वाले चुनाव में कार्यकर्ता अपना योगदान दे सकें।

मंडल प्रवासियों के दौरान 20 नेताओं को औसतन 5 विधानसभा का टास्क दिया गया था जिसमें सभी ने विधानसभाओं में जाकर शक्ति केंद्र के संयोजक, सहसंयोजक, पन्ना प्रमुख, बूथ कमिटी, समन्वय समिति से मुलाकात कर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उनकी समस्याओं को भी सुना साथ ही विधानसभा स्तर के मुद्दों को भी विस्तार से चर्चा की गयी।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस की आपसी कलह और सिर-फुटौव्वल के हालात पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता-सिंहासन से मुंह के बल गिर जाएगी, पूरे प्रदेश को अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। श्री साव ने कहा कि कांग्रेस खुद अपने कृत्यों, कलह और वादाखिलाफी के चलते छत्तीसगढ़ को कांग्रेस मुक्त प्रदेश बनाने की दिशा में चल पड़ी है और प्रदेश का जनमानस आगामी विधानसभा चुनाव में इस बात पर मुहर लगाने प्रतिबद्ध है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता जब-तब भाजपा की बेजा फिक्र में दुबले होते नजर आते हैं, जबकि पहले उन्हें अपना घर सम्हालने की जरूरत हैं। मुख्यमंत्री बघेल सत्ता के अहंकार में चूर होकर चाहे जितना बड़बोलापन प्रदर्शित कर लें, लेकिन उन्हें भी यह आभास हो गया है कि अपने शासनकाल में किए गए भ्रष्टाचार और घोटालों ने उन्हें अब अपने 'खानदानी आकाओं' से दूर कर दिया है। श्री साव ने कहा कि संभागीय सम्मेलनों से कुछ पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शैलजा का अकस्मात छत्तीसगढ़ प्रवास इसी सोच और रणनीति का हिस्सा थी ताकि मुख्यमंत्री बघेल का विकल्प तलाशा जाए। कांग्रेस के लोग अब खुद यह मानने लगे हैं कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी की अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाले ही नहीं, कांग्रेस में सत्ता और संगठन में चल रही आपसी कलह भी कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व को पलीता लगा रही है। कांग्रेस की यह कलह लगातार सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पहले ही कह दिया है कि कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कई मौकों पर अपमान का घूंट पी चुके मरकाम की पीड़ा के अपने मायने हैं, जबकि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत चाहते हैं कि मोहब्बत की एक दुकान छत्तीसगढ़ की राजनीतिक नफरतों के बाजार में भी खुलनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे मंत्री टीएस सिंहदेव तो अपने एक विभाग से इस्तीफा देकर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर हमला बोल ही चुके हैं, और अब वे भी मान रहे हैं कि सत्ता के गलियारों में संगठन की कोई अहमियत रह ही नहीं गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुंगेरीलाल की तरह सत्ता में वापसी के लाख हसीन सपने देखकर खुश होते रहें, लेकिन जमीनी सच्चाई और प्रदेश सरकार के कार्यकाल की नाकामियां इन सपनों को पंख नहीं लगाने देगी। छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटकर जिस तरह प्रदेश को कांग्रेस का एटीएम बनाने का काम पिछले साढ़े चार सालों में हुआ है, भ्रष्टाचार-घोटालों के अलावा प्रदेश के हर वर्ग के साथ प्रदेश सरकार ने जो छलावा किया है, शांति, जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था से माफियाओं ने जैसा खिलवाड़ करके जंगलराज कायम किया है, अपने इन कृत्यों के चलते कांग्रेस अपनी तयशुदा पराजय की इबारत अभी से वक्त की दीवार पर साफ-साफ पढ़ रही है। प्रदेश की जनता नवंबर में इस पर अपनी मुहर लगा देगी।

राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का बड़ा दावा

छत्तीसगढ़ में मिलेगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर

■ **राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने कहा- मेनिफेस्टो में होगा शामिल**

रायपुर। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने भिलाई पहुंचकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा, यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है तो यहां लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आने वाले कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जाएगा।

राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने मीडिया से कहा, राजस्थान में गृहिणियों को कांग्रेस 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दे रही है। इसी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए भी घोषणा कर दी है कि वहां कांग्रेस की सरकार बनी तो वहां भी 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं रेगा। यहां कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी तो यहां भी यह योजना लागू की जाएगी।

भिलाई में रंजीत रंजन ने सांसद निधि से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के सामने पावर ब्लॉक लगाने और सीसी रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुईं। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से जब पूछा गया, छत्तीसगढ़ में कितनी विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में उनके कितने विधायक हैं और इस चुनाव में कितनी सीट कांग्रेस को मिलेंगी। इसका जवाब वो नहीं दे पाईं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की 93 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के 72 विधायक हैं। जब वो आंकड़े गलत बोल गईं तो उन्होंने कहा कि उन्हें आंकड़ों में नहीं जाना। आने वाले चुनाव में कांग्रेस इसी तरह पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी।

ईडी की कार्रवाई का जवाब देगी कांग्रेस

राज्यसभा सांसद ने कहा, भाजपा की सरकार जब से केंद्र में बनी है वो ईडी की कार्रवाई के जरिए राजनीति कर रही है। ईडी की कार्रवाई में 95 प्रतिशत कांग्रेस के लोग शामिल हैं। क्या भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस के नेताओं ने किया है बीजेपी के नेताओं ने कोई करप्शन नहीं किया। भाजपा ईडी की कार्रवाई करवा रही है तो कांग्रेस भी उसका जवाब कानूनी तरीके से ही देगी।आने वाले लोकसभा चुनाव में क्क गठबंधन से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाए जाने के सवाल पर रंजीत रंजन ने कहा, 23 तारीख को पूरे विपक्ष की एक बैठक पटना में हो रही है। वहां लगभग 19 पार्टियां भाग ले रही हैं। नीतीश कुमार भी हमारे अलायंस में है। हम लोग पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को पता चल जाएगा कि यूपीए का प्रधानमंत्री का कैंडीडेट कौन होगा।

डॉ. संजय अलंग ने रायपुर संभाग आयुक्त का पदभार संभाला

रायपुर। रायपुर संभाग के नवनियुक्त आयुक्त डॉ संजय अलंग ने आज रायपुर संभाग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। डॉ अलंग सुबह रायपुर कमिश्नर कार्यालय पहुँचे और विधिवत् पदभार ग्रहण किया। डॉ अलंग इसके पहले बिलासपुर संभाग के आयुक्त थे। वे 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। कार्यालय में प्रभारी कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने नये आयुक्त का स्वागत किया और ज़िले की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी दी।संभाग आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी नये आयुक्त का स्वागत किया। पदभार संभालते ही डॉ अलंग ने पूरे कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारी- कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने सभी को जनहित में अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। कमिश्नर श्री अलंग ने स्टेनो शाखा, सीलिंग एवं भू अर्जन शाखा, उप आयुक्त कार्यालय, राजस्व न्यायालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्यालय आने वाले नागरिकों को समस्या को संवेदनशीलता के साथ सुने और यथासंभव शीघ्र समाधान करने का प्रयास करें।

बेरोजगारी भत्ता लेने वालों को मिलेगा कर्ज, 16 जून को लोन मेला

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता लेने वाले युवाओं को अब सरकार कर्ज भी देने जा रही है। यह उन्हें स्वरोजगार शुरू करने के लिए मिलेगा। इसके लिए रायपुर में 16 जून को लोन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जिले के बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हितग्राहियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अपने विभाग के स्वरोजगार मूलक योजनाओं की जानकारी और आवेदन पत्र के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

रायपुर स्थित शासकीय आईटीआई सड्डू में सुबह 11 बजे से मेले का आयोजन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से राज्य के न्यूनतम 12वीं पास और रोजगार कार्यालय में दो साल पहले से पंजीकृत युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। इस समय जिले के 4800 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। इसमें 12वीं कक्षा पास के साथ ही आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, स्नातक स्तर के युवा योजना का लाभ ले रहे हैं।

चावल घोटाले के बाद भी कांग्रेस की भूख शांत नहीं : मूणत

■ **हजारों करोड़ का चावल घोटाला**

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने प्रदेश में राशन दुकानों के मार्फत आवंटित होने वाले सरकारी चावल की लगातार चल रही कालाबाजारी पर फिर सवाल उठाया है। श्री मूणत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित मुफ्त अनाज में हजारों क्विंटल अनाज का घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की काली कमाई हजम कर जाने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के दलाल अब सरकारी चावल के लिए ऑफर तक देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ के अधिक का घोटाला कर, गरीबों का निवाला छीन कर भी कांग्रेस सरकार के लोगों को संतोष नहीं हो रहा है।

मूणत ने कहा कि सरकारी चावल की कालाबाजारी में संलिप्त दलाल अब 35 किलो चावल देने पर 600 रुपए नकद और 6 कप का ऑफर देकर खुलेआम घपलों को अंजाम दे रहे हैं और गरीबों के हक का अनाज डकार रहे हैं। श्री मूणत ने कहा कि सरकारी चावल में प्रदेश सरकार के संरक्षण में हुए घपलों की जांच केन्द्र सरकार लगातार कर रही है, लेकिन दलालों का गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। इस गोरखधंधे में दलालों के साथ राइस मिलर्स भी संलिप्त हैं। कार्डधारियों से 14 से 16 रुपए प्रतिकिलो की दर से चावल खरीदकर राइस मिलों को पहुंचाया जा रहा है। यह कालाबाजारी अमूमन सभी मोहल्लों की राशन दुकानों पर बैठे दलाल अंजाम दे रहे हैं। श्री मूणत ने कहा कि राजधानी में जब इस तरह का गोरखधंधा फल-फूल रहा है तो प्रदेश के बाकी इलाकों में इस फर्जीवाड़े का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। श्री मूणत ने कहा कि सरकारी चावल की तस्करी में अब महिलाओं की भी संलिप्तता हैरान करने वाली है, जो पुरुष दलालों के साथ मिलकर स्कूटी दुपहिया से चावल की तस्करी कर रही हैं। पीडीएस से फ्री में मिलने वाला चावल 20 रुपए किलो की दर से खरीदकर ये दलाल 35 रुपए की दर से राइस मिलर्स को बेच रहे हैं और राइस मिलर्स मिलिंग करके वही चावल 60 रुपए की दर से बेच रहे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री मूणत ने कहा कि केन्द्र सरकार और पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी में जो लोग लगे हैं, वे बेखौफ हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि ऐसे तत्वों को संरक्षण देकर प्रदेश सरकार इसमें भी अपने लिए कमीशन की गुंजाइश तलाश रही है। श्री मूणत ने कहा कि जिस पीडीएस को भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने ऊँचाइयों तक ले जाकर पारदर्शी बनाने का काम किया था और जिसके कारण छत्तीसगढ़ के पीडीएस की देशभर में मिसाल दी जाती थी।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

सरकार आपसी सर-फुटव्वल में व्यस्त, स्वस्थ्य व्यवस्था बदहाल : विजय बघेल

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद (दुर्ग) विजय बघेल ने प्रदेश की बदहाल हो चुकी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। श्री बघेल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हों, राजधानी के अंबेडकर अस्पताल के कैंसर विभाग में 18 करोड़ की पेट स्कैन मशीन छह साल से धूल खा रही हो, राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मरीजों को खुद खरीदकर लाने पर ग्लूकोज चढ़ती हो और आदिवासी बहुल जशपुरनगर जिले के सात-सात अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हों तो ऐसी दशा में भी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के दावे कर रही प्रदेश सरकार को चुल्लूभर पानी खोजने में लग जाना चाहिए। भाजपा सांसद श्री बघेल ने कहा कि पाटन विधानसभा क्षेत्र के झीट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 8 डॉक्टर्स में से अब सिर्फ 4 डॉक्टर्स ही शेष रह गए हैं, जिसके चलते मरीजों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हालात इतने बदतर हो चले हैं कि स्वयं मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र तक में पर्याप्त डॉक्टर्स नहीं हैं तो प्रदेश के अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों की बदहाली का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मोदी सरकार रोजगार देने में असफल : ठाकुर

रायपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को प्रदेश में हो रहे विभिन्न विभागों के सरकारी पदों पर भर्ती के लिए मिले आवेदनों की गिनती करने के बजाये उन्हें प्रदेश के युवाओं को बताना चाहिए कि मोदी सरकार बनाने के लिए जो भाजपा ने दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था जो अब तक नही मिला है। उल्टा मोदी सरकार की कुनीतियों के चलते प्रतिवर्ष ढाई करोड़ हाथों से रोजगार छिना गया, 9 साल में 23 करोड़ हाथ जिनके पास रोजगार था वह भी बेरोजगार हो गये। मोदी सरकार ने 9 साल में मात्र 70 हजार नियुक्ति पत्र देकर देशभर के युवाओं के साथ वादाख़िलाफ़ी किया है जबकि केंद्र में अभी 30 लाख से अधिक सरकारी पद रिक्त है जो मोदी सरकार की निजीकरण की नीति के चलते खाली है और मोदी सरकार पढ़े लिखे युवाओ को पकौड़े तलने की सलाह दे रही है। रमन सरकार के दौरान 2018 में प्रदेश में बेरोजगारी दर 22 प्रतिशत से अधिक था आज वह घटकर 1 प्रतिशत से नीचे है जो मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए रोजगार उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार देने अवसर देने का नतीजा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने रोजगार स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के माध्यम से 5 लाख युवाओं को रोजगार देने में सफलता अर्जित की है।

केंद्र सरकार ने किसानों को दिया धोखाः किसान सभा

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने लाभकारी समर्थन मूल्य के सवाल पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर फिर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। किसान सभा ने कहा है कि खरीफ सीजन 2023-24 के लिए मोदी सरकार ने विभिन्न फसलों के लिए जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है, वह अनुचित है, किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरती है और उनकी आय को भारी नुकसान पहुंचाती है। किसान सभा का कहना है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन इसके बजाय, यह घोषित एमएसपी बढ़ती इनपुट लागत के साथ किसानों के बड़े हिस्से को ऋणग्रस्तता में धकेल देगी, क्योंकि किसी भी फसल का समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले सी-2+50 फीसदी के अनुसार तय नहीं किया गया है। मोदी सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर किसानों को हो रहे नुकसान की तालिका जारी करते हुए आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा सी-2+50 प्रतिशत का फार्मूला लागू नहीं करने के कारण धान उत्पादक किसानों को लगभग 683.5 रुपये/क्विंटल का नुकसान हुआ है। यदि सरकारी अनुमान लगभग 4 टन/हेक्टेयर को उत्पादकता के रूप में गणना में लिया जाएं।

16 जून को पाटन विस में होगा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ

रायपुर । विधानसभा चुनाव 2023 के परिप्रेक्ष्य में बूथ प्रबंधन सहित विधानसभा चुनाव की तैयारी के विभिन्न पहलुओं से प्रशिक्षित कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 16 जून 2023 को सुबह 10 बजे पाटन विधानसभा क्षेत्र से शुभारंभ हो रहा है।प्रशिक्षण शिविर का दूसरा सत्र 17 जून सुबह 10 बजे राजधानी रायपुर में आयोजित होगा।18 जून को रामपुर, लोरमी, मुंगेली, कोटा, बिल्हा, बेलतरा एवं मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में तथा 19 जून को अकलतरा, जांजगीर-चांपा, जैजेपुर, पामगढ़, बलौदाबाजार एवं भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जायेगा। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से विधानसभा चुनाव के पहलुओं पर, विषयों पर विषय विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे, शिविर में प्रशिक्षार्थी के रूप में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त सेक्टर, जोन, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, विधानसभा क्षेत्र में निवासरत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं प्रदेश प्रतिनिधिगण तथा विधानसभा क्षेत्र में निवासरत निगम, मंडल, बोर्ड, आयोग में नियुक्त पदाधिकारीगण भाग लेंगे। विधानसभास्तर में प्रशिक्षित कांग्रेसजन बूथस्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।

अवैध ट्रेवल एजेंटों की गुंड़ा-गर्दी बर्दाश्त? नहींः श्रवण

रायपुर। पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन (यात्री कल्याण संघ) बुधवार 15 जून 2023 को अंतर्राज्जतयीय बस स्टैंड में हो रही गडबडियों की जांच करेगा । संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण यदु के नेतृत्व में एक टीम अंतर्राज्जंयीय बस स्टैंड में पहुंचेगी। इस दौरान यात्रियों से चर्चा कर उनके साथ हो रही मनमानी की शिकायतें दर्ज की जाएगी। यात्रियों की शिकायत पर पडताल कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यह रिपोर्ट परिवन मंत्री, परिवहन आयुक्तं, आरटीओ को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट की प्रतिलिपि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, दिल्ली भी भेजी जाएगी। पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन (यात्री कल्याण संघ) को लगातार अवैध ट्रेवल एजेंटों की गुंड़ा-गर्दी की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ दबंग किस्म के लोग और कुछ बस मालिक के स्टाफ वाले ट्रैवल्स एजेंट बनकर टिकट बुक कर रहे है और उनके पास टिकट बुक करने का कोई लाइसेंस नहीं है। वे यात्रियों को दबाव पूर्वक अपनी मर्जी से बस में बैठाते है। यात्री यदि नहीं बैठे तो मारपीट कर देते थे। यात्रियों के खिलाफ ऐसी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

प्रयास आवासीय विद्यालय के 210 बच्चों ने किया परीक्षा में क्वालीफाई

रायपुर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट अंडरग्रेजुएट के परिणाम जारी कर दिए हैं। प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के बच्चों ने इसमें शानदार प्रदर्शन किया है। इस वर्ष परीक्षा में शामिल प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 572 छात्रों में से 210 ने परीक्षा में क्वालीफाई किया है। इनमें से 08 विद्यार्थियों तथा प्रयास के ही ड्रॉपऑउट बैच के 04 छात्रों का भी एमबीबीएस में प्रवेश की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार विभाग द्वारा संचालित प्री-मेडिकल एवं प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजनांतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 85 विद्यार्थियों में से लगभग 27 का एमबीबीएस में प्रवेश संभावित है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

घोषित परीक्षा परिणाम में प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी, रायपुर का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। यहां से परीक्षा में शामिल 61 विद्यार्थियों में से 47 विद्यार्थियों ने नीट क्वालीफाई किया है। इसी प्रकार प्रयास बालक आवासीय विद्यालय, रायपुर के 55 में 17, प्रयास बिलासपुर के 63 में से 22, प्रयास अंबिकापुर के 68 में से 17, प्रयास दुर्ग के 68 में से 23, प्रयास जशपुर के 66 में से 13, प्रयास कोरबा के 55 में से 24, प्रयास कांकेर के 68 में से 28, प्रयास जगदलपुर के 68 में से 19 ने क्वालीफाई किया है। इस प्रकार कुल 572 छात्रों में से 210 छात्रों ने नीट क्वालीफाई किया है, जो कि विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार ओवरऑल 39 छात्रों के एमबीबीएस में प्रवेश होने की संभावना है, जबकि क्वालीफाई शेष विद्यार्थियों में से अनेक विद्यार्थियों को बीडीएस एवं बीएएमएस में प्रवेश मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर विभाग के सचिव डी. डी. सिंह एवं आयुक्त शम्मी आबिदी ने भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच के अधिकारियों ने मुख्य सचिव से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर । भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 के छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित अधिकारियों ने आज मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। भेंट करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 के अधिकारी सुश्री नम्रता चौबे, सहायक कलेक्टर बलौदाबाजार, प्रखर चंद्राकर सहायक कलेक्टर जिला कांकेर और सहायक कलेक्टर रायगढ़ श्री युवराज मरमट शामिल थे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संचालक टी.सी.महावर भी मौजूद थे।

तेंदूपत्ता संग्राहकों को मिलेगा 424 करोड़ से अधिक का प्रोत्साहन पारिश्रमिक

- **वर्ष 2021 का 163 करोड़ 63 लाख रुपए प्रोत्साहन पारिश्रमिक तथा वर्ष 2022 का**
- **260 करोड़ 49 लाख रुपए वितरित किये जाने विभाग ने प्रदान की अनुमति***
- **तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2021 के लिए 9 लाख 49 हजार 944 संग्राहकों को तथा तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2022 के लिए**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया जाएगा। इस संबंध में आदेश वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जारी किये हैं। विभाग ने इस संबंध में अनुमति प्रदान की है। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में लाभ में रही 733 समितियों के 9 लाख 49 हजार 944 संग्राहकों को 163 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार संग्रहण वर्ष 2022 के लिए लाभ में रहीं 661 समितियों के 8 लाख 61 हजार 772 संग्राहकों को 260 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा।

यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री अनिल कुमार राय ने दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का प्रोत्साहन पारश्रमिक संग्राहकों को वितरण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों दी जाने वाली तेंदूपत्ता संग्रहण राशि में भी वृद्धि की गई है और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.